



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2014/ आषाढ़ 27, 1936

No. 218] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2014/ASHADHA 27, 1936

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2014

दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) (चौथा संशोधन) विनियम, 2014

(2014 का 9)

सं. 6-33/2014-बी एंड सीएस.—भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना संख्या 39 के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), (iii), और (iv) और धारा 36 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो—

(ए) उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के परंतुक तथा धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(बी) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, के खंड 3 के उप-खंड (ii) में दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना सं. 39 का.आ. 44 (अ) तथा का.आ.45(अ) के तहत प्रकाशित हुई थी,—

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) विनियम, 2012 (2012 का 9) में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :-

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) (चौथा संशोधन) विनियम, 2014 (2014 का 9) कहा जाएगा।

(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) विनियम, 2012 (2012 का 09) (जिसे इसमें आगे मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 में:-

(ए) खंड (एन) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

“(एनए) “वाणिज्यिक प्रतिष्ठान” से आशय, ऐसा भवन, जहां व्यापार, व्यवसाय और कार्य किए हैं, जो प्रांसगिक अथवा अनुषंगी हो, जिसमें सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21वां) तथा पूर्त अथवा अन्य न्यास चाहे वे पंजीकृत हो अथवा नहीं, जो कोई व्यापार, व्यवसाय अथवा इससे जुड़े अथवा इससे संबंधित कार्य करते हों, जिसमें निजी लाभ के लिए चलाए जा रहे पत्रकारिता

तथा मुद्रण प्रतिष्ठान, शिक्षण, स्वास्थ्य परिचर्या अथवा अन्य संस्थान, थियेटर, सिनेमा, खानपान गृह, पब-बार, आवासीय होटल, मॉल, विमानपत्तन लाऊंज, क्लब अथवा सार्वजनिक मनोरंजन अथवा आमोद-प्रमोद के अन्य स्थान शामिल हैं, से है;”

(बी) “खंड (ओ) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

“(ओ) “**वाणिज्यिक सब्सक्राइबर**” से आशय, कोई भी व्यक्ति, जो किसी केबल ऑपरेटर अथवा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा डायरेक्ट-टु-होम ऑपरेटर अथवा हेड एण्ड-इन-द-स्काई ऑपरेटर अथवा इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, को इंगित किए गए स्थान पर प्रसारण सेवाएं या केबल सेवाएं प्राप्त करता हो और ऐसी सेवाओं को अपने ग्राहकों, उपभोक्ताओं, सदस्य अथवा अन्य व्यक्तियों के वर्ग अथवा समूह, जिनकी उसके वाणिज्यिक प्रतिष्ठान तक पहुंच है, के लाभ के लिए उपयोग करता हो, से है;”

(सी) “खंड (जेडए) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

“(जेडए) “**सब्सक्राइबर**” से आशय, एक व्यक्ति, जो एक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा केबल ऑपरेटर अथवा डायरेक्ट-टु-होम ऑपरेटर अथवा इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा प्रदाता अथवा हेड एण्ड-इन-द-स्काई ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, से उसके द्वारा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा केबल ऑपरेटर अथवा डायरेक्ट-टु-होम ऑपरेटर अथवा इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा प्रदाता अथवा हेड एण्ड-इन-द-स्काई ऑपरेटर को इंगित किए गए स्थान पर, उसे आगे किसी भी व्यक्ति को संचारित (ट्रांसमिट) किए बिना और साधारण उपभोक्ता एवं वाणिज्यिक उपभोक्ता, जब तक विशेष रूप से बाहर न रखा गया हो, प्रसारण सेवाएं या केबल सेवाएं प्राप्त करता है, से है;”

3. मूल विनियम के विनियम-4 में, उप-विनियम (3) का लोप किया जाएगा।

सुधीर गुप्ता, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./142/14]

टिप्पणी: 1 : मूल विनियमों को दिनांक 30 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना संख्या 3-24/2012-बीएण्डसीएस के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड-4 में प्रकाशित किया गया तथा इन्हें बाद में दिनांक 14 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या 3-24/2012-बीएण्डसीएस तथा दिनांक 20 सितंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या 3-24/2012-बीएण्डसीएस तथा दिनांक 10 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या 3-24/2012-बीएण्डसीएस के माध्यम से संशोधित किया गया।

टिप्पणी: 2 : व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (डिजिटल एड्रसेबल केबल टेलीविजन प्रणाली) (चौथा संशोधन) विनियम, 2014 (2014 का 9) के उद्देश्यों एवं कारणों को स्पष्ट किया गया है।

अनुलग्नक

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पृष्ठभूमि

- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को जनवरी 2004 में ‘प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं’ को विनियमित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक अंतरिम टैरिफ आदेश को 15.01.2004 को जारी किया गया था, जिसमें प्रावधान किया गया था कि 26.12.2003 को विद्यमान केबल शुल्क सम्बंधित स्तरों पर ऊपरी सीमा होंगे। इसके बाद, व्यापक विचार विमर्श के बाद, एक विस्तृत टैरिफ आदेश 01.10.2004 को जारी किया गया था। इस आदेश ने, 26.12.2003 पर प्रचलित केबल टीवी के शुल्कों की ऊपरी सीमा की वैधता को बनाए रखते हुए निर्धारित शर्तों के अधीन, नए पे-चैनलों के प्रारम्भ और विद्यमान फ्री-टु-एयर (एफटीए) चैनलों के ‘पे-चैनलों’ में रूपांतरण के लिए प्रावधान भी किया था। इन टैरिफ आदेशों का अन्तर्निहित प्रयोजन केबल टीवी शुल्कों में बारम्बार बढ़ोतरी से प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं के उपभोक्ताओं को राहत और संरक्षण देना था।
- प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं के सब्सक्राइबर (उपभोक्ता) मूल रूप से दो प्रकार के हैं – एक तरफ साधारण उपभोक्ता हैं, जो टीवी सेवाओं का उपभोग घरेलू रूप से और अपने आनन्द के लिए करते हैं, जबकि दूसरी तरफ वाणिज्यिक उपभोक्ता हैं जो उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर टीवी सेवाओं को उनके उपभोक्ताओं आदि के लाभ के लिए प्राप्त करते हैं। 2004 में टैरिफ आदेशों को जारी करते समय, जैसा ऊपर उल्लिखित है, प्राधिकरण ने, फिर भी, साधारण और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के बीच भेद नहीं किया था।
- वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ का मामला 2005 से न्यायिक जांच के अधीन है, जब होटल एवं रेस्टोरेंट संघ (पश्चिमी भारत) (एचआरएडब्ल्यूआई), जो भारतीय होटल एवं रेस्टोरेंट संघ महासंघ (एफएचआरएआई) की एक सहयोगी संगठन है, ने कुछ प्रसारकों द्वारा थोपे गए अंतरीय टैरिफों को माननीय टेलीकॉम विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के समक्ष चुनौती दी थी। माननीय टीडीसैट ने याचिकाओं को अपने निर्णय दिनांकित 17.01.2006 के माध्यम से निपटाया था, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला था कि याचिकाकर्ता संघों के उपभोक्ताओं को सदस्यों या उपभोक्ताओं के रूप में नहीं माना जा सकता है। प्राधिकरण ने इस पर विचार करने के लिए भी कहा था कि क्या वाणिज्यिक केबल टीवी उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ नियत करना आवश्यक था या नहीं।
- एक अंतरिम उपाय के रूप में, 07.03.2006 को, प्राधिकरण ने 01.10.2004 के प्रमुख टैरिफ आदेश का एक संशोधन जारी किया था। इस टैरिफ संशोधन आदेश ने शब्दों ‘साधारण केबल उपभोक्ता’ और ‘वाणिज्यिक केबल उपभोक्ता’ को परिभाषित किया था। इस बीच, माननीय टीडीसैट के उपरोक्त निर्णय पर होटल और रेस्तरां के संघों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील की गई थी। 19.10.2006 पर एक अंतरिम आदेश

में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्राधिकरण को ट्राई अधिनियम की धारा 11 के अधीन टैरिफ तैयार करने के लिए प्रक्रियाओं को, स्वतंत्र रूप से और टीडीसैट द्वारा किए गए किसी भी अवलोकन पर न निर्भर करते हुए और न ही उसके आधार पर, करने का निर्देश दिया था। 24.11.2006 को अपने अंतिम आदेश में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेशों की पुष्टि की और कहा कि वो माननीय टीडीसैट की राय से सहमत नहीं थे कि प्राधिकरण को इस पर भी विचार करना चाहिए कि क्या वाणिज्यिक केबल टीवी उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ नियत करना आवश्यक है या नहीं।

5. प्राधिकरण ने इस बीच 21.11.2006 को, माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांकित 19.10.2006 पर आधारित, दो टैरिफ संशोधन आदेशों को जारी किया था, जो क्रमशः, गैर-सीएस और सीएस क्षेत्रों में वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर लागू हैं। इस टैरिफ संशोधन आदेश ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को निम्नलिखित दो समूहों में वर्गीकृत किया, अर्थात्:-

(क) वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की एक विशिष्टीकृत श्रेणी जो निम्नलिखित से मिलकर बनी है:-

(i) 3 स्टार और उच्चतर रेटिंग वाले होटल;

(ii) हेरिटेज होटल (जैसे कि पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा परिभाषित हैं);

(iii) आवास व भोजन उपलब्ध कराने वाला और 50 या अधिक कमरे होने वाला कोई भी होटल, मोटल, सराय (इन्) या व्यावसायिक प्रतिष्ठान; और

(ख) अन्य सभी वाणिज्यिक उपभोक्ता (वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की विशिष्टीकृत श्रेणी के अंतर्गत न आने वाले)।

6. वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की विशिष्टीकृत श्रेणी के लिए केबल टीवी सेवाओं के टैरिफ को दलों द्वारा पारस्परिक रूप से निर्धारित किए जाने के लिए रखा गया था। विशिष्टीकृत श्रेणियों में न आने वाले और इस तरह दूसरी श्रेणी के अधीन आने वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को उसी शुल्क के अधीन रखा गया था, जैसा साधारण केबल उपभोक्ताओं के लिए था और इस प्रकार 26.12.2003 को प्रचलित दरों की ऊपरी सीमा को उन पर लागू किया गया था। टैरिफ संशोधन आदेश ने यह प्रावधान भी किया था कि जब कभी भी दो श्रेणियों में से किसी एक से सम्बन्धित कोई वाणिज्यिक केबल टीवी उपभोक्ता किसी प्रसारक के कार्यक्रम का उपयोग मनोरंजन कर अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी स्थान पर विशेष आयोजनों के अवसर पर पचास या अधिक व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक रूप से देखने के लिए करता है, तो टैरिफ का निर्णय सम्बन्धित पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से अवश्य करना होगा।

7. इन आदेशों के विरुद्ध भी होटल और उनके संगठनों द्वारा अपीलों [अपील संख्या 2006 की 17(सी) – ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड बनाम ट्राई एवं अन्य और अपील संख्या 2006 की 18(सी) – कर्नॉट प्रॉमिनेन्ट होटल्स लिमिटेड बनाम ट्राई एवं अन्य] के माध्यम से माननीय टीडीसैट में अपील की गई थी। टैरिफ संशोधन आदेशों दिनांकित 21.11.2006 के विरुद्ध होटलों द्वारा दायर की गई दो अपीलों में माननीय टीडीसैट ने अपना निर्णय 28.05.2010 को पारित किया था। माननीय टीडीसैट के निर्णय के परिचालनात्मक भाग में लिखा है:-

"हमारी राय, इसलिए, यह है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहाँ खण्डित किए गए आदेशों को रद्द करने की आवश्यकता है। हम तदनुसार निर्देश देते हैं। हम, फिर भी, किसी भी राशि की धन-वापसी के सम्बन्ध में कोई भी निर्देश जारी करना नहीं चाहते हैं परन्तु हम प्राधिकरण से "एक व्यापक ढंग से एक बार फिर से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मामले पर विचार करने का अनुरोध करेंगे"।

8. कुल मिलाकर, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के दो श्रेणियों में उप-वर्गीकरण को माननीय टीडीसैट द्वारा हटा दिया गया था। टीडीसैट के निर्णय दिनांकित 28.05.2010 से व्यथित, मैसर्स ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक अपील (सीए संख्या 2010 की 6040-41 – मैसर्स ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम ट्राई और अन्य) सुप्रीम कोर्ट में दायर की। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांकित 16.04.2014, इस मामले में, निम्नानुसार निर्देशित करता है:-

"... हम निर्देशित करते हैं कि खण्डित किया गया टैरिफ, जो आज की स्थिति के अनुसार प्रभावी है, तीन महीने की अवधि के लिए जारी रहेगा। कथित अवधि के भीतर, ट्राई, मामले पर नए सिरे से नजर डालेगा, जैसा कि खण्डित किए गए निर्णय में निर्देशित किया गया है, और सभी हितधारकों के दावों को सुनने के बाद टैरिफ फिर से तय करेगा।"

9. तदनुसार, जैसा कि उनके निर्णय दिनांकित 16.04.2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया था, ट्राई ने एक परामर्श प्रक्रिया शुरू की, एक नए सिरे से अभ्यास के भाग के रूप में, और हितधारकों की टिप्पणियों/ विचारों की मांग करते हुए, 11.06.2014 को एक परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श पत्र ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ शर्तों के लिए विभिन्न विकल्पों से सम्बन्धित परामर्श मुद्दों, उन्हें टीवी सेवाओं की पेशकश करने का तरीका, 'व्यावसायिक प्रतिष्ठान', 'दुकान' और 'वाणिज्यिक उपभोक्ता' की परिभाषा, और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं का समान रूप से रखे गए समूहों में उप-वर्गीकरण, पर चर्चा की और परामर्श के लिए उठाया। परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में, 24 हितधारकों ने अपने विचार/ टिप्पणियां, प्राधिकरण को प्रस्तुत कीं। बाद में, सम्बन्धित मुद्दों पर आगे चर्चा करने के लिए, एक ओपन हाउस परिचर्चा (ओएचडी) भी 4 जुलाई, 2014 को दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें 59 हितधारकों ने विचार-विमर्श में भाग लिया।
10. इस अंतःसंयोजन विनियम को, सभी सम्मिलित मुद्दों और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के विश्लेषण करने के बाद अधिसूचित किया जा रहा है।

मुद्दों का विश्लेषण

वाणिज्यिक उपभोक्ताओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानों की परिभाषा

11. वाणिज्यिक उपभोक्ता, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानों की मसौदा परिभाषाओं की चर्चा परामर्श पत्र में की गई और हितधारकों से विचार/टिप्पणियां मांगी गईं।

हितधारकों की टिप्पणियाँ

12. दो प्रमुख प्रसारकों सहित कई प्रसारक एक प्रसारण उद्योग संघ, एक होटल उद्योग संघ और साथ ही कुछ एक केबल टीवी ऑपरेटर संघ मसौदा परिभाषा के साथ मोटे तौर पर सहमत हुए। उनमें से कुछ कुछ ने इंगित किया कि 'वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों' की परिभाषा में प्रकट होने वाले 'पेशे' को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि कुछ अदालती निर्णयों ने माना है डॉक्टरों, वकीलों, इंजीनियरों आदि के परिसरों को व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं माना जाना चाहिए। कुछ अन्य प्रसारकों ने कहा है कि दुकानों, कारखानों और सार्वजनिक देखने के क्षेत्रों को 'व्यावसायिक प्रतिष्ठान' की परिभाषा में सम्मिलित किया जाना चाहिए। एक प्रसारक द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि "वाणिज्यिक प्रतिष्ठान" की परिभाषा में "प्रकाशन" को भी शामिल किया जाए। प्रसारकों के एक संघ और प्रसारकों की बिरादरी से प्रसारकों कुछ अन्य हितधारकों ने इस विचार को आगे बढ़ाया है कि किसी भी परिसर, चाहे घर के अंदर हो या बाहर हो, जो कोई घरेलू परिसर नहीं है, को व्यावसायिक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को, आवासीय उपभोक्ताओं को छोड़कर, सभी उपभोक्ताओं को सम्मिलित करने के लिए समावेशी तरीके से परिभाषित किया जाए।
13. अधिकांश वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों, केबल और डीटीएच और साथ ही होटल और रेस्तरां उद्योग के एक संघ का विचार है कि साधारण और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बीच कोई अंतर करने की कोई आवश्यकता नहीं है और सभी उपभोक्ताओं को बराबर माना जाना चाहिए। वाणिज्यिक प्रयोजन और/या वाणिज्यिक दोहन की अवधारणा को व्यावसायिक प्रतिष्ठान की परिभाषा में सम्मिलित करने का सुझाव भी दिया गया है। एक अन्य उद्योग संघ ने प्रस्तावित किया है कि वाणिज्यिक उपभोक्ता को किसी ऐसे एक के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, जो टीवी सिग्नलों का उपयोग उसके व्यापार या वाणिज्यिक गतिविधि या उसके भाग के रूप में करता है, इससे अंतर पड़े बिना कि क्या टीवी चैनलों का शुल्क दर्शकों/श्रोताओं पर लगाया है या नहीं।

विश्लेषण

14. हितधारकों के विचारों को मददे नजर रखकर, 'व्यावसायिक प्रतिष्ठान' की परिभाषा को सम्मिलित किया गया है और 'वाणिज्यिक सब्सक्राइबर' की परिभाषा को तदनुसार संशोधित किया गया है। यह वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ प्रावधानों और उन्हें टेलीविजन सेवाओं की पेशकश करने के तरीकों के अनुरूप है, जिनकी चर्चा अगले पैराग्राफों में की गई है।

वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ

15. परामर्श पत्र में, हितधारकों के विचारों/टिप्पणियों की मांग करते हुए, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ विहित करने के लिए निम्न चार विकल्पों पर विचार विमर्श किया गया:—

- (1) वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ साधारण उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ के समान है।
- (2) वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ की साधारण उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ के साथ एक सम्बंध है।
- (3) वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ की साधारण उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ के साथ कोई सम्बंध नहीं है परन्तु सभी हितधारकों की संरक्षा करने के लिए निर्धारित किए गए कुछ सुरक्षा उपाय हैं जैसे कि अनिवार्य अ-ला-कार्टे पेशकश, चैनल-समूह के दरों के साथ-साथ विकृत अ-ला-कार्टे मूल्य निर्धारण को रोकने के लिए शर्तें आदि।
- (4) वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ को सम्पूर्ण बाजार की शक्तियों के अधीन रखा गया है।

हितधारकों की टिप्पणियाँ

16. होटल उद्योग के संघों और लगभग सभी वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) ने परामर्श पत्र में चर्चा किए गए पहले विकल्प को अंगीकार करने के लिए वकालत की है अर्थात् वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ साधारण उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित टैरिफ के समान होना चाहिए। उनके दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए, मुख्य रूप से निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं— (i) अंतिम उपभोक्ता/दर्शक एक ही है चाहे टीवी सेवाओं का लाभ उपभोक्ता के घरेलू परिसर में उठाया जाता है या किसी होटल या अस्पताल या किसी भी अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में, (ii) कोई उपभोक्ता इस तरह के वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में विशेष रूप से टीवी चैनलों को देखने के लिए नहीं जाता है (iii) दोनों मामलों में विषय-वस्तु के उत्पादन और इसके वितरण के लिए प्रसारक के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है और साथ ही सिग्नल की विषय-वस्तु/गुणवत्ता भी समान रहती है। उनमें से कुछ ने आगे कहा कि, ऐसे मामलों में, जहां उपभोक्ता किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में विशेष रूप से टीवी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जाता है और इसके लिए भुगतान करता है, तो उनके लिए टैरिफ साधारण उपभोक्ताओं के टैरिफ से अलग हो सकता है।
17. जबकि दूसरी तरफ, सभी प्रसारक और उनके प्रतिनिधि निकाय यह विचार रखते हैं कि चौथे विकल्प, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ को बाजार की शक्तियों पर छोड़ने, को अंगीकार किया जाए। उनके द्वारा इस सम्बंध में प्रस्तुत मुख्य तर्क हैं — (i) टीवी सेवाएँ मूल रूप से गैर-ज़रूरी सेवाएँ हैं और इसलिए, इन्हें विनियमित किए जाने की आवश्यकता नहीं है, (ii) कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए अंतरीय मूल्य निर्धारण किया जाता है, (iii) वाणिज्यिक उपभोक्ता वाणिज्यिक लाभ के लिए टीवी सिग्नलों का दोहन करते हैं, इसलिए, प्रसारक उस लाभ के एक उचित भाग के लिए अधिकृत हैं। ओएचडी के दौरान एक प्रश्न के प्रत्युत्तर में, प्रसारकों के एक संघ ने दर्शाया है कि ऐसे वाणिज्यिक उपभोक्ताओं जिनके बारे में टेलीविजन की सदस्यता लेना 'ज्ञात' है, के कुल राजस्व का कुल वितरण राजस्व का 1.5-2.2 प्रतिशत होने का अनुमान है।
18. एक एचआईटीएस ऑपरेटर ने दूसरे विकल्प को निर्धारित करने का सुझाव दिया, जो यह प्रावधान करता है कि साधारण और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ के बीच कुछ सम्बंध होना चाहिए। एक प्रसारक और कुछ एक केबल ऑपरेटर संघों ने तीसरे विकल्प के लिए उनकी वरीयता व्यक्त की है। एक एमएसओ द्वारा यह सुझाव भी दिया गया है कि प्रसारक को वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की अलग श्रेणी के लिए उनके

चैनलों की खुदरा मूल्य को निर्धारित करना चाहिए और मूल्य श्रृंखला में विभिन्न हितधारकों के लिए राजस्व के अंश को ट्राई द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

विश्लेषण

19. अंतिम उपभोक्ता, चाहे उसके घरेलू परिसरों में या किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर, सिग्नलों की उसी गुणवत्ता के साथ उसी विषय-वस्तु को देख पाता है। दोनों ही मामलों में, विषय-वस्तु के स्वामी (प्रसारक) और डीपीओ के लिए लागत, सिग्नलों की आपूर्ति करने के लिए, सहज रूप से, इस तथ्य के कारण से बदलती नहीं है कि सिग्नलों की आपूर्ति घरेलू परिसरों या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में की जाती है। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपील (सिविल) 2006 का 2061 होटल और रेस्टोरेंट संघ और एएनआर बनाम स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य में अपने निर्णय दिनांकित 24.11.2006 में, दूसरों के बीच, निम्नानुसार अवलोकन किया था:—

"... होटलों के स्वामी उनके उपभोक्ताओं/ अतिथियों के लिए टीवी सिग्नलों को लेते हैं। ऐसा करते समय, वे अन्य बातों के साथ उनके उपभोक्ताओं को सेवाएँ प्रदान करते हैं। किसी होटल का स्वामी अपने उपभोक्ताओं को विभिन्न सुख-साधनों, जैसे कि बिस्तर, भोजन, पंखे, टेलीविजन, आदि प्रदान करता है। इस तरह की सुविधा या सुख-साधनों का विस्तार, रहने वालों के लिए, करने के लिए कोई प्रावधान करना किसी स्वामी द्वारा किसी अतिथि के लिए एक बिक्री का गठन नहीं करेगा। होटल के स्वामी उसी तरीके से प्रसारकों से टीवी सिग्नलों को लेते हैं, जैसे वे लाइसेंसधारियों से विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति लेते हैं। कोई अतिथि बिजली के किसी उपकरण का उपयोग कर सकता है। यह होटल द्वारा उसे बिजली की बिक्री का गठन नहीं करेगा। कथित प्रयोजन के लिए, 'उपभोक्ता' और 'उपभोक्ता' होटल और उसका प्रबंधन होना जारी रहेंगे। इसी प्रकार, यदि कोई टेलीविजन सेट सभी कमरों में प्रदान किया जाता है, एक सुख-साधन के मार्ग से प्रबंधन द्वारा दी गई सेवाओं के भाग के रूप में, जिसके लिए अतिथियों पर अलग से शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो वह किसी होटल में रहने वाले अतिथियों को ग्राहकों या उपभोक्ताओं में परिवर्तित नहीं करेगा...."

कथित निर्णय इसी तरह के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय के एक अन्य निर्णय (पंजाब राज्य बनाम मैसर्स एसोसिएटेड होटल ऑफ इंडिया लिमिटेड [(1972) 1 एससीसी 472] को आगे उद्धरित करता है, जो नीचे पुनः उद्धरित किया गया है:—

"... जब कोई यात्री, विमान से या भाप के जहाज से, अपने यात्रा-टिकट को खरीदता है तो लेन-देन एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसकी यात्रा के लिए एक है। यदि, उस लेन-देन को करने के दौरान, यात्री को पेयों या भोजनों या सिगरेटों की आपूर्ति की जाती है, तो कोई भी नहीं सोचेगा कि लेन-देन में अलग बिक्रियाँ सम्मिलित हैं, जब हर बार उनमें से किसी भी चीज की आपूर्ति की जाती है। लेन-देन अनिवार्य रूप से यात्री को उसके गंतव्य तक ले जाने का एक है और यदि ले जाने के अनुबंध के प्रदर्शन में उसे किसी वस्तु की आपूर्ति की जाती है, तो इस तरह की आपूर्ति उन सेवाओं के लिए केवल आकस्मिक है, यह अनुबंध के स्वरूप या फिर प्रकृति को बदलती नहीं है। इसी प्रकार से, जब कपड़ों को किसी लॉण्ड्री को धोने के लिए दिया जाता है, तो वहाँ एक लेन-देन है, जिसमें काम या सेवा अनिवार्य रूप से सम्मिलित है, और यदि लॉण्ड्रीवाला किसी पोशाक का कोई बटन टांक देता है, जो गिर गया है, तो बटन या धागे की कोई बिक्री नहीं है। विषय-वस्तु के आकस्मिक उपयोगों को सम्मिलित करने वाले इस तरह के कई मामलों, को उद्धृत किया जा सकता है जिनमें से किसी को भी मुख्य लेन-देन के भाग के रूप में किसी बिक्री को सम्मिलित करना नहीं कहा जा सकता है।"

20. माननीय उच्चतम न्यायालय की ऊपर की गई टिप्पणियों से, यह स्पष्ट है कि किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में टीवी सेवाओं का वह प्रावधान सेवा के लिए केवल आकस्मिक है, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने उपभोक्ताओं को प्रदान कर रहा है। इसे टीवी सेवाओं के किसी पुनर्वितरण या पुनर्बिक्री के अर्थ में नहीं बताया जा सकता है। कुल मिलाकर उपभोक्ता कौन है, इस निर्णय के मामले से इसका निपटान कर दिया गया है। उक्त निर्णय के माध्यम से इस बात का भी निपटान कर दिया गया है कि सुविधा के माध्यम से किसी आगन्तुक को प्रदान की गई सेवा, जहाँ आगन्तुक से इसके लिए अलग से कोई शुल्क नहीं वसूला जाता है, उसे आगन्तुक को सेवा की बिक्री नहीं समझा जाएगा। आगे, यह निर्णय विचाराधीन विषय से सीधे संबंधित है। तदनुसार, प्राधिकरण का यह विचार है कि टीवी सेवाओं की दरों को लेकर साधारण उपभोक्ता या वाणिज्यिक उपभोक्ता के बीच कोई अन्तरीकरण नहीं होना चाहिए, अर्थात् दोनों ही मामलों में, दरों को समान होना चाहिए और वह प्रति सेट टॉप बॉक्स के आधार पर होना चाहिए। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, एट्रेसेबल प्रणालियों के लिए लागू टैरिफ आदेश अर्थात् दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एट्रेसेबल प्रणालियाँ) टैरिफ आदेश, 2010 के खंड-6 को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है।

21. फिर भी, ऐसे मामले में जब, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान उसके परिसरों में चैनलों को देखने के लिए अपने उपभोक्ताओं/आगंतुकों पर विशेष रूप से अतिरिक्त शुल्क लगाता है, तो प्रसारकों के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठान के इस तरह के राजस्व में किसी अंश के लिए एक मामला है। इसलिए, जहाँ वाणिज्यिक प्रतिष्ठान विशेष रूप से टीवी सेवाएँ प्रदान करने के लिए अपने ग्राहकों से अतिरिक्त राजस्व अर्जित कर रहा है, दरों को प्रसारक और वाणिज्यिक उपभोक्ता के बीच आपसी मोलभावों पर आधारित होना चाहिए। ऐसे मामलों में भी, वाणिज्यिक उपभोक्ता को केवल किसी डीपीओ/केबल ऑपरेटर के माध्यम से टीवी चैनल के इस तरह के सिग्नलों को प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। तदनुसार, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एट्रेसेबल प्रणालियाँ) टैरिफ आदेश, 2010 के खंड-6 में उप-खंड(5) जोड़ा गया है।

वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टीवी चैनलों की पेशकश करने का तरीका

22. वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को टीवी चैनलों की पेशकश करने के तीन मॉडलों की चर्चा परामर्श पत्र में की गई थी। प्रथम मॉडल में यह परिकल्पना की गई है कि वाणिज्यिक उपभोक्ता, प्रसारक के साथ करार कर स्वयं प्रसारक अथवा प्रसारक द्वारा विनिर्दिष्ट डीपीओ से सिग्नल प्राप्त करें। दूसरे मॉडल में, वाणिज्यिक उपभोक्ता, डीपीओ के साथ करार कर सिग्नल प्राप्त करेंगे। जबकि डीपीओ तथा प्रसारकों की आपस में सहमतिपूर्ण व्यवस्था होगी। परामर्श पत्र में चर्चा किया गया तीसरा मॉडल, पहले तथा दूसरे मॉडल का संयोजन है।

हितधारकों की टिप्पणियाँ

23. लगभग सभी प्रसारकों और उनके प्रतिनिधि निकायों और एजेंटों ने कहा है कि केवल मॉडल (i) व्यवहार्य है और इसे अंगीकार किया जाना चाहिए। पहले मॉडल के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया का सुझाव देते हुए, उन्होंने तर्क दिया है कि — (क) दूसरा मॉडल वाणिज्यिक उपभोक्ताओं

को सिग्नल नहीं मिलने के लिए प्रवृत्त है, यदि प्रसारकों और डीपीओ के बीच मोलभाव नहीं हो पाया और (ख) तीसरा मॉडल भ्रम के लिए प्रवृत्त है क्योंकि प्रसारकों और डीपीओ, दोनों को संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ) को प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी।

24. लगभग सभी डीपीओ ने दूसरे मॉडल को अंगीकार करने का सुझाव दिया है। कुछ एक केबल टीवी ऑपरेटर संघों ने विचार व्यक्त किया है कि विनियामक को अधिकतम खुदरा मूल्य नियत करना चाहिए, जिसके आधार पर प्रसारकों और डीपीओ आरआईओ बनाएँ। फिर भी, प्रसारकों को डीपीओ की पहचान नहीं करनी चाहिए, जिसके माध्यम से वाणिज्यिक उपभोक्ता को प्रसारक के सिग्नल मिलने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में जहाँ वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के पास अपने स्वयं के हेडएण्ड हैं, प्रसारक आरआईओ के अनुसार वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के साथ सीधे मोलभाव कर सकते हैं। एक अन्य केबल ऑपरेटर संघ ने कहा है कि प्रसारक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को दोनों का मोलभाव करना चाहिए जबकि डीपीओ को सेवाएँ उसी दर पर देनी चाहिए, जो साधारण उपभोक्ता के लिए है।
25. होटल और रेस्तरां उद्योग संघों में से एक ने कहा है कि पहले मॉडल को अंगीकार नहीं किया जाना चाहिए, जबकि एक होटल उद्योग संघ ने तीसरे मॉडल के लिए अपनी पसंद जाहिर की है।

विश्लेषण

26. भारत में टीवी चैनलों की डाउनलिकिंग के लिए दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

“5.6 आवेदक कंपनी (प्रसारक), उपग्रह टीवी चैनल सिग्नल रिसेप्शन डीकोडरों को केवल एमएसओ/केबल ऑपरेटरों को, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अधीन पंजीकृत हैं या भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए डीटीएच दिशानिर्देशों के अधीन पंजीकृत किसी डीटीएच ऑपरेटर को या उनके विद्यमान टेलीकॉम लाइसेंस के अधीन विधिवत अनुमत या दूरसंचार विभाग द्वारा अधिकृत किसी इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा प्रदाता को या इस तरह की सेवा प्रदान करने के लिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एचआईटीएस ऑपरेटरों के लिए नीतिगत दिशानिर्देश के अधीन विधिवत अनुमत किसी एचआईटीएस ऑपरेटर को प्रदान करेगा।”

अतः, प्रसारक अपने सिग्नलों को सीधे उपभोक्ताओं, जिनमें वाणिज्यिक उपभोक्ता शामिल हैं, को नहीं दे सकता। प्रसारकों को सिग्नलों की आपूर्ति किसी डीपीओ के माध्यम से करनी होगी। यदि कोई वाणिज्यिक उपभोक्ता टीवी सिग्नलों को उसके क्षेत्र में परिचालन करने वाले किसी भी एमएसओ या उससे सम्बंधित स्थानीय केबल ऑपरेटर/डीटीएच ऑपरेटर/एचआईटीएस आदि ऑपरेटरों से प्राप्त कर सकता है, तो यह बाजार में प्रतिस्पर्धा को भी सुनिश्चित करेगा। तदनुसार, ‘सब्सक्राइबर’ की परिभाषा को भी उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है।

वाणिज्यिक उपभोक्ताओं का उप-वर्गीकरण

27. परामर्श पत्र में, समान प्रकार से रखे गए समूहों में वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के उप-वर्गीकरण और टैरिफ को उस प्रकार से नियत करने के मुद्दे के बारे में चर्चा की गई और हितधारकों के विचारों की मांग की गई। लगभग सभी हितधारकों का विचार यह था कि किसी भी तरह का ऐसा उप-वर्गीकरण और टैरिफ को उस प्रकार से नियत करना आगे बढ़ने की दिशा में उपयुक्त नहीं हो सकता है।

विश्लेषण

28. वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को टेलीविजन सिग्नलों की पेशकश करने के तरीके के संबंध में टैरिफ प्रावधान तथा उपबंधों के मद्देनजर, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ विहित करने के प्रावधान के प्रयोजनार्थ समान समूहबद्ध करने हेतु, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को उप-श्रेणीबद्ध किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपेक्षित भेद के अनुसार, वाणिज्यिक उपभोक्ता को मुख्यतः दो वर्गों में रखा गया है :- (1) जो अपने आगन्तुकों को सुविधाओं के भाग के रूप में टेलीविजन सेवाओं/कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं, (2) जो उपर्युक्त पैरा 21 में यथा-चर्चा की गई पद्धति के माध्यम से इसे प्रभारित करते हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, विनियम 4 के उप-विनियम 3 को हटा दिया गया है।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2014

THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE SERVICES) INTERCONNECTION (DIGITAL ADDRESSABLE CABLE TELEVISION SYSTEMS) (FOURTH AMENDMENT) REGULATION, 2014

(No. 9 of 2014)

No. 6-33/2014- B&CS. —In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub-clauses (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Government of India, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunication) No.39,—

(a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government by proviso to clause (k) of sub-section (1) of section 2 and clause (d) of sub-section (1) of section 11 of the said Act, and

(b) published under notification No. 39 (S.O. 44 (E) and 45 (E)) dated the 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II- Section 3- Sub-section (ii), ----

the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) Regulations 2012 (9 of 2012), namely:—

1. (1) These regulations may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) (Fourth Amendment) Regulation, 2014 (9 of 2014).
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In regulation 2 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) Regulations, 2012 (9 of 2012), (hereinafter referred to as the principal regulations),---
(a) after the clause (n), the following clause shall be inserted, namely:—
“(na) “commercial establishment” means any premises wherein any trade, business or any work in connection with, or incidental or ancillary thereto, is carried on and includes a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), and charitable or other trust, whether registered or not, which carries on any business, trade or work in connection with, or incidental or ancillary thereto, journalistic, printing and publishing establishments, educational, healthcare or other institutions run for private gain, theatres, cinemas, restaurants, eating houses, pubs, bars, residential hotels, malls, airport lounges, clubs or other places of public amusements or entertainment;”
(b) for clause (o), the following clause shall be substituted, namely:—
“(o) “commercial subscriber” means any person who receives broadcasting services or cable services at a place indicated by him to a cable operator or multi system operator or direct to home operator or head end in the sky operator or Internet Protocol television service provider, as the case may be, and uses such services for the benefit of his clients, customers, members or any other class or group of persons having access to his commercial establishment;”
(c) for the clause (za), the following clause shall be substituted, namely.—
“(za) “subscriber” means a person who receives broadcasting services or cable services from a multi system operator or cable operator or direct to home operator or Internet Protocol television service provider or head end in the sky operator at a place indicated by him to the multi-system operator or cable operator or direct to home operator or Internet Protocol television service provider or head end in the sky operator, as the case may be, without further transmitting it to any person and includes ordinary subscribers and commercial subscribers, unless specifically excluded;”
3. In regulation 4 of the principal regulations, sub-regulation (3) shall be deleted.

SUDHIR GUPTA, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./142/14]

Note.1.—The principal regulation was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* its notification No. 3- 24/2012- B&CS, dated the 30th April, 2012 and subsequently amended *vide* notifications No. 3-24/2012- B&CS dated the 14th May, 2012, No. 3-24/2012-B&CS, dated the 20th September, 2013 and No. 3-24/2012- B&CS, dated the 10th February, 2014.

Note.2.—The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Digital Addressable Cable Television Systems) (Fourth Amendment) Regulation, 2014 (9 of 2014).

Annexure

Explanatory Memorandum

Background

1. The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) was entrusted with the responsibility of regulating ‘broadcasting and cable TV’ services in January, 2004. An interim Tariff Order was issued on 15.01.2004, which provided that the cable charges prevailing on 26.12.2003 shall be the ceilings at the respective levels. Thereafter, following extensive consultations, a detailed Tariff Order was issued on 01.10.2004. This order, while maintaining the sanctity of the ceiling of cable TV charges prevailing on 26.12.2003, also provided a window for introduction of new pay channels and conversion of existing Free-to-Air (FTA) channels to ‘pay channels’ subject to prescribed conditions. The underlying objective of these Tariff orders was to give relief and protection to consumers of broadcasting and cable TV services from frequent hikes in cable TV charges.

2. Subscribers of broadcasting and cable TV services are basically of two kinds. First, there are ordinary subscribers who consume TV services domestically for their own pleasure. The second group comprises commercial subscribers who obtain TV services for the benefit of their clients, customers etc., at their commercial establishment. While issuing the Tariff Orders in 2004, as mentioned above, the Authority, however, did not differentiate between ordinary and commercial subscribers.
3. The matter pertaining to tariffs for commercial subscribers has been under judicial scrutiny since 2005, before the Hon'ble Telecom Disputes Settlement Appellate Tribunal (TDSAT), when Hotels and Restaurants Association (Western India) (HRAWI), a sister association of Federation of Hotel and Restaurant Associations of India (FHRAI), challenged differential tariffs imposed by some broadcasters. The Hon'ble TDSAT disposed of these petitions *vide* its judgment dated 17.01.2006 wherein it concluded that the members of the petitioner associations couldn't be regarded as subscribers or consumers. It also asked the Authority to consider whether it was necessary or not to fix tariff for commercial cable TV subscribers.
4. As an interim measure, on 07.03.2006, the Authority issued an amendment to the principal Tariff Order of 01.10.2004. This Tariff Amendment Order defined the terms 'Ordinary cable subscriber' and 'Commercial cable subscriber'. In the meanwhile, the aforesaid judgment of the Hon'ble TDSAT was appealed by the Associations of Hotels and Restaurants before the Hon'ble Supreme Court. In an interim order on 19.10.2006, the Hon'ble Supreme Court directed the Authority to carry out the processes for framing the tariff under Section 11 of the TRAI Act, independently and not relying on or on the basis of any observation made by TDSAT. In its final order on 24.11.2006, the Hon'ble Supreme Court confirmed its interim orders and stated that it did not agree with the opinion of the Hon'ble TDSAT that the Authority should also consider whether it is necessary or not to fix tariff for commercial cable TV subscribers.
5. Based on the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 19.10.2006, the Authority issued two Tariff Amendment Orders, on 21.11.2006, applicable to commercial subscribers in non-CAS and CAS areas, respectively. This tariff amendment order categorized commercial subscribers into the following two groups, namely:—
 - (a) A specified category of commercial subscribers comprising---
 - (i) Hotels with rating of 3 stars and above;
 - (ii) Heritage hotels (as defined by the Department of Tourism, Government of India);
 - (iii) Any hotel, motel, inn or commercial establishment providing board & lodging and having 50 or more rooms; and
 - (b) All other commercial subscribers (not falling under the specified category of commercial subscribers).
6. The tariff for cable TV services for the specified category of commercial subscribers was to be mutually determined by the parties. However, the tariff for commercial subscribers not falling in the specified categories (coming under the second category) was subject to the same charges as ordinary cable subscribers and thus the ceiling of rates prevailing as on 26.12.2003 was made applicable to them. The tariff amendment order also provided that whenever a commercial cable TV subscriber belonging to either of the two categories uses the programme of a broadcaster for public viewing by fifty or more persons on the occasion of special events at a place registered under the Entertainment Tax Act, the tariff will have to be mutually decided between the parties concerned.
7. These orders too were appealed against in the Hon'ble TDSAT by way of appeals [Appeal No.17(C) of 2006 - East India Hotel Ltd. Vs. TRAI & Ors. and Appeal No. 18 (C) of 2006 - The Connaught Prominent Hotels Limited vs. TRAI & Ors. by the hotels and their associations. The Hon'ble TDSAT passed its judgment on 28.05.2010 in the two appeals filed by the hotels against the tariff amendment orders dated 21.11.2006. The operative portion of the judgment of the Hon'ble TDSAT read:

"We, therefore, are of the opinion that it is a fit case where the impugned orders are required to be set aside. We direct accordingly. We, however, do not wish to issue any direction with regard to the refund of any amount but we would request the Authority to consider the case of commercial establishments once over again in a broad based manner".
8. In sum, the sub-classification of commercial consumers into two categories was struck down by the Hon'ble TDSAT. Aggrieved by the TDSAT judgement dated 28.05.2010, M/s. ESPN Software India Pvt. Ltd. filed an appeal (CA No. 6040-41 of 2010 -M/s. ESPN Software India Pvt. Ltd. Vs. TRAI and Ors.) in the Supreme Court. The judgment of the Hon'ble Supreme Court, dated 16.04.2014, in this case, directs as follows:

“..... we direct that for a period of three months, the impugned tariff, which is in force as on today, shall continue. Within the said period, TRAI shall look into the matter de novo, as directed in the impugned judgment, and shall re-determine the tariff after hearing the contentions of all the stake holders....”

9. Accordingly, as directed by the Hon'ble Supreme Court in its judgment dated 16.04.2014, TRAI initiated a consultation process, as part of a de novo exercise, and issued a Consultation Paper (CP) on 11.06.2014 seeking comments/views of the stakeholders. The CP discussed and raised related consultation issues pertaining to various alternatives for tariff stipulations for the commercial subscribers, manner of offering of TV services to them, the definition of the 'commercial establishment', 'shop' and 'commercial subscriber', and sub-categorization of the commercial subscribers into similarly placed groups. In response to the CP, 24 stakeholders submitted their views/comments to the Authority. Subsequently, to further discuss the issues involved, an Open House Discussion (OHD) was also held at Delhi on 4th July, 2014, wherein 59 stakeholders participated in the discussions.
10. This interconnection regulation is being notified after analyzing all the issues involved and the inputs received from various stakeholders.

Analysis of Issues

Definition of commercial subscribers, commercial establishment and shops

11. Draft definitions of commercial subscriber, commercial establishment and shops were discussed in the CP and views/comments of the stakeholders were solicited.

Stakeholder comments

12. Several broadcasters including the two prominent broadcasters, a broadcasting industry association, a Hotel industry association as well as a couple of cable TV operator associations have broadly agreed with the draft definitions. Some of them have pointed out that the 'profession' appearing in the definition of 'commercial establishments' should be deleted as some court decisions have held that the premises of doctors, lawyers, engineers etc. should not be considered commercial establishments. Some other broadcasters have stated that shops, factories and public viewing areas should be included in the definition of 'commercial establishment'. It was also suggested by a broadcaster that 'publishing' should also be included in the definition of 'commercial establishments'. An association of broadcasters and some other stakeholders from the broadcasters fraternity have put forth the view that any premise, indoor or outdoor, that is not a domestic premise should be categorized as commercial and commercial subscribers be defined in an all inclusive manner to include all subscribers except residential subscribers.
13. The majority of the distribution platform operators, cable and DTH, as well as a hotel and restaurant industry association are of the view that there is no need to make a distinction between ordinary and commercial subscribers and all subscribers should be treated at par. It has also been suggested to include the concept of commercial purpose and/or commercial exploitation into the definition of commercial establishment. Another industry association has proposed that commercial subscriber should be defined as the one who uses TV signals as its business or commercial activity or part thereof, irrespective of whether TV channels are charged or not from the viewers/audience.

Analysis

14. Taking into account the views of the stakeholders, the definition of 'commercial establishment' has been included and the definition of 'commercial subscriber' has been accordingly amended. This is also in line with the tariff prescription and the manner of offering of television services to the commercial subscribers, which have been discussed in subsequent paragraphs.

Tariff for Commercial subscribers

15. In the CP, the following four alternatives were discussed for prescribing tariff for commercial subscribers, seeking views/comments of the stakeholders:
 - (i) The tariff for commercial subscribers is the same as that for ordinary subscribers.
 - (ii) The tariff for commercial subscribers has a linkage with the tariff for ordinary subscribers.
 - (iii) The tariff for commercial subscribers has no linkage with the tariff for ordinary subscribers but there are some protective measures prescribed to protect all the stakeholders such as mandatory a-la-carte offering, conditions to prevent perverse a-la-carte pricing vis-à-vis bouquet rates etc.
 - (iv) The tariff for commercial subscribers is kept under total forbearance.

Stakeholder comments

16. Hotel industry associations and almost all distribution platform operators (DPOs) have advocated for adoption of the first alternative discussed in the CP i.e. the tariff for commercial subscribers should be same as that prescribed for the ordinary subscribers. To support their view, the main arguments put forth have been — (i) the ultimate consumer/viewer is the same whether the TV services are availed at the domestic premises of the consumer or in a hotel or hospital or any other commercial establishment, (ii) a consumer does not go to such commercial establishment specifically to view TV channels (iii) there is no extra cost to the broadcaster for production of content and its distribution in both the cases and the content/quality of signal remains the same. Some of them further stated that, in cases where the consumer goes to a commercial establishment specifically to avail TV services and pays for it, the tariff may be different from that for the ordinary subscribers.
17. On the other hand, all broadcasters and their representative bodies are of the view that the fourth alternative, prescribing total forbearance on tariff for commercial subscribers, be adopted. The main arguments presented by them in this regard are — (i) the TV services are basically non-essential services and, therefore, need not be regulated, (ii) in many international markets, differential pricing is done for the commercial subscribers, (iii) commercial subscribers exploit the TV signals for commercial gains, therefore, the broadcasters are entitled to a fair share of the same. In response to a query during the OHD, an Association of broadcasters has indicated that the total revenue of the commercial subscribers that are 'known' to subscribe to television are estimated at 1.5-2.2% of total distribution revenues.
18. A headend in the sky (HITS) operator has suggested for prescription of the second alternative which provides that there should be a certain linkage between the tariff for ordinary and commercial subscribers. A broadcaster and a couple of cable operator associations have expressed their preference for the third alternative. It has also been suggested by a multi system operator (MSO) that a broadcaster should prescribe the retail price of its channels for different categories of commercial subscribers and the revenue share for different stakeholders in the value chain should be determined by TRAI.

Analysis

19. The end consumer, whether at his domestic premises or at any commercial establishment, gets to view the same content with same quality of signals. In both the cases, the cost to the content owner (broadcaster) and the DPO, for supplying the signals, per se, does not vary on account of where the signals are supplied - at the domestic premises or the commercial establishment. Moreover, The Hon'ble Supreme Court in its judgment dated 24.11.2006 in appeal (Civil) 2061 of 2006 Hotel and Restaurants Association and Anr Vs Star India Pvt. Ltd. and Ors has, amongst others, observed as under:

"....The owners of the hotels take TV signals for their customers/ guests. While doing so, they inter alia provide services to their customers. An owner of a hotel provides various amenities to its customers such as beds, meals, fans, television, etc. Making a provision for extending such facilities or amenities to the boarders would not constitute a sale by an owner to a guest. The owners of the hotels take TV signals from the broadcasters in the same manner as they take supply of electrical energy from the licensees. A guest may use an electrical appliance. The same would not constitute the sale of electricity by the hotel to him. For the said purpose, the 'consumer' and 'subscriber' would continue to be the hotel and its management. Similarly, if a television set is provided in all the rooms, as part of the services rendered by the management by way of an amenity, wherefor the guests are not charged separately, the same would not convert the guests staying in a hotel into consumers or subscribers....."

The said judgment further quotes another judgment of the Hon'ble Supreme Court (in The State of Punjab v. M/s. Associated Hotels of India Ltd. [(1972) 1 SCC (472)]) on similar issue, which is reproduced as under:

".... When a traveller, by plane or by steam-ship, purchases his passage-ticket, the transaction is one for his passage from one place to another. If, in the course of carrying out that transaction, the traveller is supplied with drinks or meals or cigarettes, no one would think that the transaction involves separate sales each time any of those things is supplied. The transaction is essentially one of carrying the passenger to his destination and if in performance of the contract of carriage something is supplied to him, such supply is only incidental to that services, not changing either the pattern or the nature of the contract. Similarly, when clothes are given for washing to a laundry, there is a transaction which essentially involves work or service, and if the laundryman stitches a button to a garment which has fallen off, there is no sale of the button or the thread. A number of such cases involving incidental uses of materials can be cited, none of which can be said to involve a sale as part of the main transaction."

20. From the observations of the Hon'ble Supreme Court, cited above, it is clear that provision of TV services in a commercial establishment is only incidental to the service that the commercial establishment is providing to its clients. It cannot be construed as re-distribution or re-sale of TV services. In any case, there is no

re-transmission. In sum, the question as to who is the subscriber has been settled through this judgment. It has also been settled by the said judgment that any service rendered to a guest by way of an amenity, wherefor the guests are not charged separately, the same would not constitute as sale of the said service to the guest. Further, this judgment specifically refers to the subject in hand. **Accordingly, the Authority was of the view that in the rates of TV services, there should be no differentiation between an ordinary subscriber and a commercial subscriber i.e. in both the cases, the charges should be the same and on per set top box basis.** In view of the above, clause 6 of the tariff order applicable for addressable systems namely, the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2010, has been suitably amended.

21. However, in case, the commercial establishment specifically charges extra to its clients/visitors on account of viewing of channels at its premises, there is a case for broadcasters to have a share in such revenue of the commercial establishment. Therefore, where the commercial establishment is earning extra revenue from its clients specifically on account of providing TV services, the rates should be based on mutual negotiations between the broadcaster and the commercial subscriber. In such cases also, the commercial subscriber would be required to obtain such signals of TV channel through a DPO/cable operator only. Accordingly, sub-clause (5) has been added to clause 6 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2010.

Manner of offering TV channels to the commercial subscribers

22. Three models of offering of TV channels to commercial subscribers were discussed in the CP. The first model envisages that the commercial subscriber enters into agreement with the broadcaster and obtains signals either from the broadcaster itself or a DPO designated by the broadcaster. In the second model, the commercial subscriber is to enter into agreement with the DPO and obtain the signals while DPO and broadcasters have their own mutually agreed arrangements. The third model discussed in the CP is a combination of the first and second models.

Stakeholder Comments

23. Almost all the broadcasters and their representative bodies and agents have stated that only the first model is viable and should be adopted. While suggesting a detailed procedure for implementation of this model they have reasoned that – (a) the second model is prone to commercial subscribers not getting signal because of potential breakdown of negotiations between broadcasters and DPOs and (b) the third model is prone to confusion, as both broadcasters and DPOs would be allowed to provide Reference Interconnect Offers (RIOs).
24. Almost all the DPOs have suggested adoption of second model. A couple of cable TV operator associations have opined that the regulator should fix the MRP based on which the broadcasters and DPOs make the RIO. However, broadcasters should not identify the DPO through which the commercial subscriber should get the signals of the broadcaster. They have also stated that in cases where commercial subscribers have their own headend, the broadcasters can directly negotiate with the commercial subscribers as per RIO. Another cable operator association has stated that the broadcaster and commercial subscribers should negotiate the rates while the DPO should give the services at the same rate as for ordinary subscriber.
25. One of the hotel and restaurant industry associations has stated the first model should not be adopted, while another hotel industry association has expressed its preference for the third model.

Analysis

26. The guideline for downlinking of TV channels in India prescribe as under:

“5.6. The applicant company shall provide Satellite TV Channel signal reception decoders only to MSOs/Cable Operators registered under the Cable Television Networks (Regulation) Act 1995 or to a DTH operator registered under the DTH guidelines issued by Government of India or to an Internet Protocol Television (IPTV) Service Provider duly permitted under their existing Telecom License or authorized by Department of Telecommunications or to a HITS operator duly permitted under the policy guidelines for HITS operators issued by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India to provide such service.”

So, the broadcaster cannot supply signals directly to subscribers, including the commercial subscribers. Broadcasters should supply their signals through a DPO. It would also ensure competition in the market if a commercial subscriber can obtain TV signals from any MSO or its linked local cable operator /DTH operator etc. operating in his area. Accordingly, definition of ‘subscriber’ has also been suitably amended.

Sub-categorization of commercial subscribers

27. In the CP, the issue regarding sub-categorization of commercial subscribers into similarly placed groups and fixing the tariff therefor was discussed and views of the stakeholders were sought. Almost all the stakeholders,

across all the segments, are of the view that any such sub-categorization and fixing of tariff for such sub-categories may not be the appropriate way forward.

Analysis

28. In view of the tariff prescription and the provisions regarding manner of offering of TV signals to the commercial subscribers, there is no need for sub-categorization of the commercial subscribers into similarly placed groups for the purpose of prescription of tariff dispensation for commercial subscribers. The only distinction required is to place the commercial subscribers into two broad classes – (i) those who offer television services/programmes as part of amenities to their guests and (ii) those who charge for the same in the manner as discussed in para 21 above. In view of the above, the sub-regulation 3 of regulation 4 has been deleted.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2014

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश, 2014

(2014 का 6)

सं. 1-19/2014-बीएंडसीएस .- भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना संख्या 39 के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), (iii), (iv) और (v) और उप-खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो—

(ए) उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के परंतुक तथा धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(बी) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, के खंड 3 के उप-खंड (ii) में दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना सं० 39 (एस.ओ. 44 (ई) तथा 45(ई)) के तहत प्रकाशित हुई थी,—

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2010 (2010 का 01) में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, नामतः :-

1. (1) इस आदेश को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश, 2014 (2014 का 6) कहा जाएगा।
(2) यह आदेश सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणाली) टैरिफ आदेश, 2010(2010 का 01) (जिसे इसमें आगे मूल टैरिफ आदेश कहा गया है) के खंड 3 में:-

(ए) उप-खंड (ण) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड (णक) अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

“(णक) “वाणिज्यिक प्रतिष्ठान” से आशय, ऐसा भवन, जहां व्यापार, व्यवसाय और कार्य किए हैं, जो प्रांसगिक अथवा अनुषंगी हो, जिसमें सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21वां) तथा पूर्ण अथवा अन्य न्यास चाहे वे पंजीकृत हो अथवा नहीं, जो कोई व्यापार, व्यवसाय अथवा इससे जुड़े अथवा इससे संबंधित कार्य करते हो, जिसमें निजी लाभ के लिए चलाए जा रहे पत्रकारिता तथा मुद्रण प्रतिष्ठान, शिक्षण, स्वास्थ्य परिचर्या अथवा अन्य संस्थान, थियेटर, सिनेमा, खानपान गृह, पब-बार, आवासीय होटल, मॉल, विमानपत्तन लाऊंज, क्लब अथवा सार्वजनिक मनोरंजन अथवा आमोद-प्रमोद के अन्य स्थान शामिल हैं, से है;”

(बी) प्रतिस्थापित किए गए उप-खंड (णक) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड(णख) अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

“(णख) “वाणिज्यिक सब्सक्राइबर” से आशय, कोई भी व्यक्ति, जो किसी केबल ऑपरेटर अथवा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा डायरेक्ट-टु-होम ऑपरेटर अथवा हेडएण्ड-इन-द-स्काई ऑपरेटर अथवा इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, को इंगित किए गए स्थान पर प्रसारण सेवाएं या केबल सेवाएं प्राप्त करता हो और ऐसी सेवाओं को अपने ग्राहकों, उपभोक्ताओं, सदस्य अथवा अन्य व्यक्तियों के वर्ग अथवा समूह, जिनकी उसके वाणिज्यिक प्रतिष्ठान तक पहुंच है, के लाभ के लिए उपयोग करता हो,से है;”

(सी) उप-खंड (य) के लिए, निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

“(य) “साधारण सब्सक्राइबर” से आशय, कोई भी सब्सक्राइबर, जो एक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा केबल ऑपरेटर अथवा डायरेक्ट-टु-होम ऑपरेटर अथवा अथवा इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा प्रदाता अथवा हेडएण्ड-इन-द-स्काई ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, से प्रसारण सेवाएं या केबल सेवाएं प्राप्त करता है तथा उसका प्रयोग अपने घरेलू उपयोग के लिए करता है, से है;”

(डी) उप-खंड (यड.) के लिए, निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

“(युड.) “सब्सक्राइबर” से आशय, एक व्यक्ति, जो एक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा केबल ऑपरेटर अथवा डायरेक्ट-टु-होम ऑपरेटर अथवा इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा प्रदाता अथवा हेडएण्ड-इन-द-स्काई ऑपरेटर से उसके द्वारा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा केबल ऑपरेटर अथवा डायरेक्ट-टु-होम ऑपरेटर अथवा इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा प्रदाता अथवा हेडएण्ड-इन-द-स्काई ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, को इंगित किए गए स्थान पर, उसे आगे किसी भी व्यक्ति को संचारित (ट्रांसमिट) किए बिना और जिसमें साधारण सब्सक्राइबर एवं वाणिज्यिक सब्सक्राइबर शामिल हैं, जिन्हें जब तक विशेष रूप से बाहर न रखा गया हो, प्रसारण सेवाएं या केबल सेवाएं प्राप्त करता है, से है; ”

3. मूल टैरिफ आदेश के खंड-6 में, —

(ए) “साधारण” जहां भी वर्णित हो, का लोप किया जाएगा;

(बी) उप-खंड (4) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड एवं स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

“(5) यदि कोई वाणिज्यिक सब्सक्राइबर अपने ग्राहक अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उसके परिसर में दिखाए गए किसी प्रसारक के कार्यक्रम के लिए शुल्क वसूलता है, तो ऐसी सेवा उपलब्ध कराने से पूर्व उस प्रसारक के साथ करार करेगा तथा प्रसारक, ऐसे कार्यक्रम के लिए वाणिज्यिक सब्सक्राइबर से प्रभार वसूलेगा, जो उनकी आपसी सहमति से तय होगा;

स्पष्टीकरण : संदेह दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उप-खंड (5) में संदर्भित किसी भी कार्यक्रम के प्रसारण की अवधि के दौरान, वाणिज्यिक सब्सक्राइबर द्वारा उपलब्ध करायी जा रही वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में किसी भी प्रकार की वृद्धि को उक्त कार्यक्रम के लिए प्रभार माना जाएगा।”

सुधीर गुप्ता, सचिव

[विज्ञापन III / 4 / असा. / 142 / 14.]

टिप्पणी:-1 : मूल टैरिफ आदेश को दिनांक 21 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या 11-14/2009-बीएण्डसीएस के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया तथा इन्हें बाद में दिनांक 30 अप्रैल, 2012 की अधिसूचना संख्या 1-9/2012-बीएण्डसीएस और दिनांक 20 सितंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या 1-12/2012-बीएण्डसीएस तथा दिनांक 10 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या 1-9/2012-बीएण्डसीएस के माध्यम से संशोधित किया गया।

टिप्पणी:-2 : व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रसेबल प्रणाली) टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश, 2014 (2014 का 6) के उद्देश्यों एवं कारणों को स्पष्ट किया गया है।

अनुलग्नक

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पृष्ठभूमि

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को जनवरी 2004 में ‘प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं’ को विनियमित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक अंतरिम टैरिफ आदेश को 15.01.2004 को जारी किया गया था, जिसमें प्रावधान किया गया था कि 26.12.2003 को विद्यमान केबल शुल्क सम्बंधित स्तरों पर ऊपरी सीमा होंगे। इसके बाद, व्यापक विचार विमर्श के बाद, एक विस्तृत टैरिफ आदेश 01.10.2004 को जारी किया गया था। इस आदेश ने, 26.12.2003 पर प्रचलित केबल टीवी के शुल्कों की ऊपरी सीमा की वैधता को बनाए रखते हुए निर्धारित शर्तों के अधीन, नए पे-चैनलों के प्रारम्भ और विद्यमान फ्री-टु-एयर (एफटीए) चैनलों के ‘पे-चैनलों’ में रूपांतरण के लिए प्रावधान भी किया था। इन टैरिफ आदेशों का अन्तर्निहित प्रयोजन केबल टीवी शुल्कों में बारम्बार बढ़ोतरी से प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं के उपभोक्ताओं को राहत और संरक्षण देना था।
2. प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं के सब्सक्राइबर (उपभोक्ता) मूल रूप से दो प्रकार के हैं — एक तरफ साधारण उपभोक्ता हैं, जो टीवी सेवाओं का उपभोग घरेलू रूप से और अपने आनन्द के लिए करते हैं, जबकि दूसरी तरफ वाणिज्यिक उपभोक्ता हैं जो उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर टीवी सेवाओं को उनके उपभोक्ताओं आदि के लाभ के लिए प्राप्त करते हैं। 2004 में टैरिफ आदेशों को जारी करते समय, जैसा ऊपर उल्लिखित है, प्राधिकरण ने, फिर भी, साधारण और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के बीच भेद नहीं किया था।
3. वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ का मामला 2005 से न्यायिक जांच के अधीन है, जब होटल एवं रेस्टोरेंट संघ (पश्चिमी भारत) (एचआरएडब्ल्यूआई), जो भारतीय होटल एवं रेस्टोरेंट संघ महासंघ (एफएचआरएआई) की एक सहयोगी संगठन है, ने कुछ प्रसारकों द्वारा थोपे गए अंतरीय टैरिफों को माननीय टेलीकॉम विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के समक्ष चुनौती दी थी। माननीय टीडीसैट ने याचिकाओं को अपने निर्णय दिनांकित 17.01.2006 के माध्यम से निपटारा था, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला था कि याचिकाकर्ता संघों के उपभोक्ताओं को सदस्यों या उपभोक्ताओं के रूप में नहीं माना जा सकता है। प्राधिकरण ने इस पर विचार करने के लिए भी कहा था कि क्या वाणिज्यिक केबल टीवी उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ नियत करना आवश्यक था या नहीं।
4. एक अंतरिम उपाय के रूप में, 07.03.2006 को, प्राधिकरण ने 01.10.2004 के प्रमुख टैरिफ आदेश का एक संशोधन जारी किया था। इस टैरिफ संशोधन आदेश ने शब्दों ‘साधारण केबल सब्सक्राइबर’ और ‘वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर’ को परिभाषित किया था। इस बीच, माननीय टीडीसैट के उपरोक्त निर्णय पर होटल और रेस्तरां के संघों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील की गई थी। 19.10.2006 पर एक अंतरिम आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्राधिकरण को ट्राई अधिनियम की धारा 11 के अधीन टैरिफ तैयार करने के लिए प्रक्रियाओं को, स्वतंत्र रूप

से और टीडीसैट द्वारा किए गए किसी भी अवलोकन पर न निर्भर करते हुए और न ही उसके आधार पर, करने का निर्देश दिया था। 24.11.2006 को अपने अंतिम आदेश में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेशों की पुष्टि की और कहा कि वो माननीय टीडीसैट की राय से सहमत नहीं थे कि प्राधिकरण को इस पर भी विचार करना चाहिए कि क्या वाणिज्यिक केबल टीवी उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ़ नियत करना आवश्यक है या नहीं।

5. प्राधिकरण ने इस बीच 21.11.2006 को, माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांकित 19.10.2006 पर आधारित, दो टैरिफ़ संशोधन आदेशों को जारी किया था, जो क्रमशः, गैर-सीएस और सीएस क्षेत्रों में वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर लागू हैं। इस टैरिफ़ संशोधन आदेश ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को निम्नलिखित दो समूहों में वर्गीकृत किया, अर्थात्:-

(क) वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की एक विशिष्टीकृत श्रेणी जो निम्नलिखित से मिलकर बनी है:-

- (i) 3 स्टार और उच्चतर रेटिंग वाले होटल;
- (ii) हेरिटेज होटल (जैसे कि पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा परिभाषित हैं);
- (iii) आवास व भोजन उपलब्ध कराने वाला और 50 या अधिक कमरे होने वाला कोई भी होटल, मोटल, सराय (इन्) या व्यावसायिक प्रतिष्ठान; और

(ख) अन्य सभी वाणिज्यिक उपभोक्ता (वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की विशिष्टीकृत श्रेणी के अंतर्गत न आने वाले)।

6. वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की विशिष्टीकृत श्रेणी के लिए केबल टीवी सेवाओं के टैरिफ़ को दलों द्वारा पारस्परिक रूप से निर्धारित किए जाने के लिए रखा गया था। विशिष्टीकृत श्रेणियों में न आने वाले और इस तरह दूसरी श्रेणी के अधीन आने वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को उसी शुल्क के अधीन रखा गया था, जैसा साधारण केबल उपभोक्ताओं के लिए था और इस प्रकार 26.12.2003 को प्रचलित दरों की ऊपरी सीमा को उन पर लागू किया गया था। टैरिफ़ संशोधन आदेश ने यह प्रावधान भी किया था कि जब कभी भी दो श्रेणियों में से किसी एक से सम्बन्धित कोई वाणिज्यिक केबल टीवी उपभोक्ता किसी प्रसारक के कार्यक्रम का उपयोग मनोरंजन कर अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी स्थान पर विशेष आयोजनों के अवसर पर पचास या अधिक व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक रूप से देखने के लिए करता है, तो टैरिफ़ का निर्णय सम्बन्धित पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से अवश्य करना होगा।

7. इन आदेशों के विरुद्ध भी होटल और उनके संगठनों द्वारा अपीलों (अपील संख्या 2006 की 17(सी) – ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड बनाम ट्राई एवं अन्य और अपील संख्या 2006 की 18(सी) – कनॉट प्रॉमिनेन्ट होटल्स लिमिटेड बनाम ट्राई एवं अन्य) के माध्यम से माननीय टीडीसैट में अपील की गई थी। टैरिफ़ संशोधन आदेशों दिनांकित 21.11.2006 के विरुद्ध होटलों द्वारा दायर की गई दो अपीलों में माननीय टीडीसैट ने अपना निर्णय 28.05.2010 को पारित किया था। माननीय टीडीसैट के निर्णय के परिचालनात्मक भाग में लिखा है:-

"हमारी राय, इसलिए, यह है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहाँ खण्डित किए गए आदेशों को रद्द करने की आवश्यकता है। हम तदनुसार निर्देश देते हैं। हम, फिर भी, किसी भी राशि की धन-वापसी के सम्बन्ध में कोई भी निर्देश जारी करना नहीं चाहते हैं परन्तु हम प्राधिकरण से 'एक व्यापक ढंग से एक बार फिर से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मामले पर विचार करने का अनुरोध करेंगे'।

8. कुल मिलाकर, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के दो श्रेणियों में उप-वर्गीकरण को माननीय टीडीसैट द्वारा हटा दिया गया था। टीडीसैट के निर्णय दिनांकित 28.05.2010 से व्यथित, मैसर्स ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक अपील (सीए संख्या 2010 की 6040-41 – मैसर्स ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम ट्राई और अन्य) सुप्रीम कोर्ट में दायर की। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांकित 16.04.2014, इस मामले में, निम्नानुसार निर्देशित करता है:-

"... हम निर्देशित करते हैं कि खण्डित किया गया टैरिफ़, जो आज की स्थिति के अनुसार प्रभावी है, तीन महीने की अवधि के लिए जारी रहेगा। कथित अवधि के भीतर, ट्राई, मामले पर नए सिरे से नज़र डालेगा, जैसा कि खण्डित किए गए निर्णय में निर्देशित किया गया है, और सभी हितधारकों के दावों को सुनने के बाद टैरिफ़ फिर से तय करेगा... "

9. तदनुसार, जैसा कि उनके निर्णय दिनांकित 16.04.2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया था, ट्राई ने एक परामर्श प्रक्रिया शुरू की, एक नए सिरे से अभ्यास के भाग के रूप में, और हितधारकों की टिप्पणियों/ विचारों की मांग करते हुए, 11.06.2014 को एक परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श पत्र ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ़ शर्तों के लिए विभिन्न विकल्पों से सम्बन्धित परामर्श मुद्दों, उन्हें टीवी सेवाओं की पेशकश करने का तरीका, 'व्यावसायिक प्रतिष्ठान', 'दुकान' और 'वाणिज्यिक सब्सक्राइबर' की परिभाषा, और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं का समान रूप से रखे गए समूहों में उप-वर्गीकरण, पर चर्चा की और परामर्श के लिए उठाया। परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में, 24 हितधारकों ने अपने विचार/ टिप्पणियाँ, प्राधिकरण को प्रस्तुत कीं। बाद में, सम्बन्धित मुद्दों पर आगे चर्चा करने के लिए, एक ओपन हाउस परिचर्चा (ओएचडी) भी 4 जुलाई 2014 को दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें 59 हितधारकों ने विचार-विमर्श में भाग लिया।

10. इस टैरिफ़ आदेश को, सभी सम्मिलित मुद्दों और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के विश्लेषण करने के बाद अधिसूचित किया जा रहा है।

मुद्दों का विश्लेषण

वाणिज्यिक उपभोक्ताओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानों की परिभाषा

11. वाणिज्यिक उपभोक्ता, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानों की मसौदा परिभाषाओं की चर्चा परामर्श पत्र में की गई और हितधारकों से विचार/टिप्पणियां मांगी गई।

हितधारकों की टिप्पणियाँ

12. दो प्रमुख प्रसारकों सहित कई प्रसारक एक प्रसारण उद्योग संघ, एक होटल उद्योग संघ और साथ ही कुछ एक केबल टीवी ऑपरेटर संघ मसौदा परिभाषा के साथ मोटे तौर पर सहमत हुए। उनमें से कुछ कुछ ने इंगित किया कि 'वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों' की परिभाषा में प्रकट होने वाले 'पेशे' को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि कुछ अदालती निर्णयों ने माना है डॉक्टरों, वकीलों, इंजीनियरों आदि के परिसरों को व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं माना जाना चाहिए। कुछ अन्य प्रसारकों ने कहा है कि दुकानों, कारखानों और सार्वजनिक देखने के क्षेत्रों को 'व्यावसायिक प्रतिष्ठान' की परिभाषा में सम्मिलित किया जाना चाहिए। एक प्रसारक द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि "वाणिज्यिक प्रतिष्ठान" की परिभाषा में "प्रकाशन" को भी शामिल किया जाए। प्रसारकों के एक संघ और प्रसारकों की बिरादरी से प्रसारकों कुछ अन्य हितधारकों ने इस विचार को आगे बढ़ाया है कि किसी भी परिसर, चाहे घर के अंदर हो या बाहर हो, जो कोई घरेलू परिसर नहीं है, को व्यावसायिक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को, आवासीय उपभोक्ताओं को छोड़कर, सभी उपभोक्ताओं को सम्मिलित करने के लिए समावेशी तरीके से परिभाषित किया जाए।
13. अधिकांश वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों, केबल और डीटीएच और साथ ही होटल और रेस्तरां उद्योग के एक संघ का विचार है कि साधारण और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बीच कोई अंतर करने की कोई आवश्यकता नहीं है और सभी उपभोक्ताओं को बराबर माना जाना चाहिए। वाणिज्यिक प्रयोजन और/या वाणिज्यिक दोहन की अवधारणा को व्यावसायिक प्रतिष्ठान की परिभाषा में सम्मिलित करने का सुझाव भी दिया गया है। एक अन्य उद्योग संघ ने प्रस्तावित किया है कि वाणिज्यिक उपभोक्ता को किसी ऐसे एक के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, जो टीवी सिग्नलों का उपयोग उसके व्यापार या वाणिज्यिक गतिविधि या उसके भाग के रूप में करता है, इससे अंतर पड़े बिना कि क्या टीवी चैनलों का शुल्क दर्शकों/श्रोताओं पर लगाया है या नहीं।

विश्लेषण

14. हितधारकों के विचारों को मददे नजर रखकर, 'व्यावसायिक प्रतिष्ठान' की परिभाषा को सम्मिलित किया गया है और 'वाणिज्यिक सब्सक्राइबर' की परिभाषा को तदनुसार संशोधित किया गया है। यह वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ प्रावधानों और उन्हें टेलीवजन सेवाओं की पेशकश करने के तरीके को अनुरूप है, जिनकी चर्चा अगले पैराग्राफों में की गई है।

वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ

15. परामर्श पत्र में, हितधारकों के विचारों/टिप्पणियों की मांग करते हुए, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ विहित करने के लिए निम्न चार विकल्पों पर विचार विमर्श किया गया:—

- (1) वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ साधारण उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ के समान है।
- (2) वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ की साधारण उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ के साथ एक सम्बन्ध है।
- (3) वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ की साधारण उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु सभी हितधारकों की संरक्षा करने के लिए निर्धारित किए गए कुछ सुरक्षा उपाय हैं जैसे कि अनिवार्य अ-ला-कार्ट पेशकश, चैनल-समूह के दरों के साथ-साथ विकृत अ-ला-कार्ट मूल्य निर्धारण को रोकने के लिए शर्तें आदि
- (4) वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ को सम्पूर्ण बाजार की शक्तियों के अधीन रखा गया है।

हितधारकों की टिप्पणियाँ

16. होटल उद्योग के संघों और लगभग सभी वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) ने परामर्श पत्र में चर्चा किए गए पहले विकल्प को अंगीकार करने के लिए वकालत की है अर्थात् वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ साधारण उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित टैरिफ के समान होना चाहिए। उनके दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए, मुख्य रूप से निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं— (i) अंतिम उपभोक्ता/दर्शक एक ही है चाहे टीवी सेवाओं का लाभ उपभोक्ता के घरेलू परिसर में उठाया जाता है या किसी होटल या अस्पताल या किसी भी अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में, (ii) कोई उपभोक्ता इस तरह के वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में विशेष रूप से टीवी चैनलों को देखने के लिए नहीं जाता है (iii) दोनों मामलों में विषय-वस्तु के उत्पादन और इसके वितरण के लिए प्रसारक के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है और साथ ही सिग्नल की विषय-वस्तु/गुणवत्ता भी समान रहती है। उनमें से कुछ ने आगे कहा कि, ऐसे मामलों में, जहां उपभोक्ता किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में विशेष रूप से टीवी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जाता है और इसके लिए भुगतान करता है, तो उनके लिए टैरिफ साधारण उपभोक्ताओं के टैरिफ से अलग हो सकता है।
17. जबकि दूसरी तरफ, सभी प्रसारक और उनके प्रतिनिधि निकाय यह विचार रखते हैं कि चौथे विकल्प, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ को बाजार की शक्तियों पर छोड़ने, को अंगीकार किया जाए। उनके द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत मुख्य तर्क हैं — (i) टीवी सेवाएँ मूल रूप से गैर-ज़रूरी

सेवाएँ हैं और इसलिए, इन्हें विनियमित किए जाने की आवश्यकता नहीं है, (ii) कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए अंतरीय मूल्य निर्धारण किया जाता है, (iii) वाणिज्यिक उपभोक्ता वाणिज्यिक लाभ के लिए टीवी सिग्नलों का दोहन करते हैं, इसलिए, प्रसारक उस लाभ के एक उचित भाग के लिए अधिकृत हैं। ओएचडी के दौरान एक प्रश्न के प्रत्युत्तर में, प्रसारकों के एक संघ ने दर्शाया है कि ऐसे वाणिज्यिक उपभोक्ताओं जिनके बारे में टेलीविजन की सदस्यता लेना 'ज्ञात' है, के कुल राजस्व का कुल वितरण राजस्व का 1.5–2.2 प्रतिशत होने का अनुमान है।

18. एक एचआईटीएस ऑपरेटर ने दूसरे विकल्प को निर्धारित करने का सुझाव दिया, जो यह प्रावधान करता है कि साधारण और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ के बीच कुछ सम्बंध होना चाहिए। एक प्रसारक और कुछ एक केबल ऑपरेटर संघों ने तीसरे विकल्प के लिए उनकी वरीयता व्यक्त की है। एक एमएसओ द्वारा यह सुझाव भी दिया गया है कि प्रसारक को वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की अलग श्रेणी के लिए उनके चैनलों की खुदरा मूल्य को निर्धारित करना चाहिए और मूल्य श्रृंखला में विभिन्न हितधारकों के लिए राजस्व के अंश को ट्राई द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

विश्लेषण

19. अंतिम उपभोक्ता, चाहे उसके घरेलू परिसरों में या किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर, सिग्नलों की उसी गुणवत्ता के साथ उसी विषय-वस्तु को देख पाता है। दोनों ही मामलों में, विषय-वस्तु के स्वामी (प्रसारक) और डीपीओ के लिए लागत, सिग्नलों की आपूर्ति करने के लिए, सहज रूप से, इस तथ्य के कारण से बदलती नहीं है कि सिग्नलों की आपूर्ति घरेलू परिसरों या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में की जाती है। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपील (सिविल) 2006 का 2061 होटल और रेस्टोरेंट संघ और एएनआर बनाम स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य में अपने निर्णय दिनांकित 24.11.2006 में, दूसरों के बीच, निम्नानुसार अवलोकन किया था:—

"... होटलों के स्वामी उनके उपभोक्ताओं/अतिथियों के लिए टीवी सिग्नलों को लेते हैं। ऐसा करते समय, वे अन्य बातों के साथ उनके उपभोक्ताओं को सेवाएँ प्रदान करते हैं। किसी होटल का स्वामी अपने उपभोक्ताओं को विभिन्न सुख-साधनों, जैसे कि बिस्तर, भोजन, पंखे, टेलीविजन, आदि प्रदान करता है। इस तरह की सुविधा या सुख-साधनों का विस्तार, रहने वालों के लिए, करने के लिए कोई प्रावधान करना किसी स्वामी द्वारा किसी अतिथि के लिए एक बिक्री का गठन नहीं करेगा। होटल के स्वामी उसी तरीके से प्रसारकों से टीवी सिग्नलों को लेते हैं, जैसे वे लाइसेंसधारियों से विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति लेते हैं। कोई अतिथि बिजली के किसी उपकरण का उपयोग कर सकता है। यह होटल द्वारा उसे बिजली की बिक्री का गठन नहीं करेगा। कथित प्रयोजन के लिए, 'उपभोक्ता' और 'उपभोक्ता' होटल और उसका प्रबंधन होना जारी रहेंगे। इसी प्रकार, यदि कोई टेलीविजन सेट सभी कमरों में प्रदान किया जाता है, एक सुख-साधन के मार्ग से प्रबंधन द्वारा दी गई सेवाओं के भाग के रूप में, जिसके लिए अतिथियों पर अलग से शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो वह किसी होटल में रहने वाले अतिथियों को ग्राहकों या उपभोक्ताओं में परिवर्तित नहीं करेगा....."

कथित निर्णय इसी तरह के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय के एक अन्य निर्णय (पंजाब राज्य बनाम मैसर्स एसोसिएटेड होटल ऑफ इंडिया लिमिटेड ((1972) 1 एससीसी 472)) को आगे उद्धरित करता है, जो नीचे पुनः उद्धरित किया गया है:—

"... जब कोई यात्री, विमान से या भाप के जहाज से, अपने यात्रा-टिकट को खरीदता है तो लेन-देन एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसकी यात्रा के लिए एक है। यदि, उस लेन-देन को करने के दौरान, यात्री को पेयों या भोजनों या सिगरेटों की आपूर्ति की जाती है, तो कोई भी नहीं सोचेगा कि लेन-देन में अलग बिक्रियाँ सम्मिलित हैं, जब हर बार उनमें से किसी भी चीज की आपूर्ति की जाती है। लेन-देन अनिवार्य रूप से यात्री को उसके गंतव्य तक ले जाने का एक है और यदि ले जाने के अनुबंध के प्रदर्शन में उसे किसी वस्तु की आपूर्ति की जाती है, तो इस तरह की आपूर्ति उन सेवाओं के लिए केवल आकस्मिक है, यह अनुबंध के स्वरूप या फिर प्रकृति को बदलती नहीं है। इसी प्रकार से, जब कपड़ों को किसी लॉण्ड्री को धोने के लिए दिया जाता है, तो वहाँ एक लेन-देन है, जिसमें काम या सेवा अनिवार्य रूप से सम्मिलित है, और यदि लॉण्ड्रीवाला किसी पोशाक का कोई बटन टांक देता है, जो गिर गया है, तो बटन या धागे की कोई बिक्री नहीं है। विषय-वस्तु के आकस्मिक उपयोगों को सम्मिलित करने वाले इस तरह के कई मामलों, को उद्धृत किया जा सकता है जिनमें से किसी को भी मुख्य लेन-देन के भाग के रूप में किसी बिक्री को सम्मिलित करना नहीं कहा जा सकता है।"

20. माननीय उच्चतम न्यायालय की ऊपर की गई टिप्पणियों से, यह स्पष्ट है कि किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में टीवी सेवाओं का वह प्रावधान सेवा के लिए केवल आकस्मिक है, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने उपभोक्ताओं को प्रदान कर रहा है। इसे टीवी सेवाओं के किसी पुनर्वितरण या पुनर्बिक्री के अर्थ में नहीं बताया जा सकता है। कुल मिलाकर उपभोक्ता कौन है, इस निर्णय के मामले से इसका निपटान कर दिया गया है। उक्त निर्णय के माध्यम से इस बात का भी निपटान कर दिया गया है कि सुविधा के माध्यम से किसी आगन्तुक को प्रदान की गई सेवा, जहाँ आगन्तुक से इसके लिए अलग से कोई शुल्क नहीं वसूला जाता है, उसे आगन्तुक को सेवा की बिक्री नहीं समझा जाएगा। आगे, यह निर्णय विचाराधीन विषय से सीधे संबंधित है। तदनुसार, प्राधिकरण का यह विचार है कि टीवी सेवाओं, की दरों को लेकर साधारण उपभोक्ता या वाणिज्यिक उपभोक्ता के बीच कोई अन्तरीकरण नहीं होना चाहिए, अर्थात् दोनों ही मामलों में, दरों को समान होना चाहिए और वह प्रति सेट टॉप बाक्स (एसटीबी) के आधार पर होना चाहिए। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, टैरिफ आदेश के खंड-6 को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है।

21. फिर भी, ऐसे मामले में जब, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान उसके परिसरों में चैनलों को देखने के लिए अपने उपभोक्ताओं/आगंतुकों पर विशेष रूप से अतिरिक्त शुल्क लगाता है, तो प्रसारकों के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठान के इस तरह के राजस्व में किसी अंश के लिए एक मामला है। इसलिए, जहाँ वाणिज्यिक प्रतिष्ठान विशेष रूप से टीवी सेवाएँ प्रदान करने के लिए अपने ग्राहकों से अतिरिक्त राजस्व अर्जित कर रहा है, दरों को प्रसारक और वाणिज्यिक उपभोक्ता के बीच आपसी मोलभावों पर आधारित होना चाहिए। ऐसे मामलों में भी, वाणिज्यिक उपभोक्ता को केवल किसी डीपीओ/केबल ऑपरेटर के माध्यम से टीवी चैनल के इस तरह के सिग्नलों को प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए एड्रसेबल तथा

गैर-एड्रैसेबल प्रणाली, दोनों के लिए लागू टैरिफ आदेश में उपयुक्त रूप से संशोधन किया गया है। तदनुसार, इस संशोधित टैरिफ आदेश के माध्यम से खंड-6 में उप-खंड(5) जोड़ा गया है।

वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टीवी चैनलों की पेशकश करने का तरीका

22. वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को टीवी चैनलों की पेशकश करने के तीन मॉडलों की चर्चा परामर्श पत्र में की गई थी। प्रथम मॉडल में यह परिकल्पना की गई है कि वाणिज्यिक उपभोक्ता, प्रसारक के साथ करार कर स्वयं प्रसारक अथवा प्रसारक द्वारा विनिर्दिष्ट डीपीओ से सिग्नल प्राप्त करें। दूसरे मॉडल में, वाणिज्यिक उपभोक्ता, डीपीओ के साथ करार कर सिग्नल प्राप्त करेंगे। जबकि डीपीओ तथा प्रसारकों की आपस में सहमतिपूर्ण व्यवस्था होगी। परामर्श पत्र में चर्चा किया गया तीसरा मॉडल, पहले तथा दूसरे मॉडल का संयोजन है।

हितधारकों की टिप्पणियाँ

23. लगभग सभी प्रसारकों और उनके प्रतिनिधि निकायों और एजेंटों ने कहा है कि केवल मॉडल (i) व्यवहार्य है और इसे अंगीकार किया जाना चाहिए। पहले मॉडल के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया का सुझाव देते हुए, उन्होंने तर्क दिया है कि – (क) दूसरा मॉडल वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सिग्नल नहीं मिलने के लिए प्रवृत्त है, यदि प्रसारकों और डीपीओ के बीच मोलभाव नहीं हो पाया और (ख) तीसरा मॉडल भ्रम के लिए प्रवृत्त है क्योंकि प्रसारकों और डीपीओ, दोनों को संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ) को प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी।
24. लगभग सभी डीपीओ ने दूसरे मॉडल को अंगीकार करने का सुझाव दिया है। कुछ एक केबल टीवी ऑपरेटर संघों ने विचार व्यक्त किया है कि विनियामक को अधिकतम खुदरा मूल्य नियत करना चाहिए, जिसके आधार पर प्रसारकों और डीपीओ आरआईओ बनाएँ। फिर भी, प्रसारकों को डीपीओ की पहचान नहीं करनी चाहिए, जिसके माध्यम से वाणिज्यिक उपभोक्ता को प्रसारक के सिग्नल मिलने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में जहाँ वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के पास अपने स्वयं के हेडएण्ड हैं, प्रसारक आरआईओ के अनुसार वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के साथ सीधे मोलभाव कर सकते हैं। एक अन्य केबल ऑपरेटर संघ ने कहा है कि प्रसारक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को दरों का मोलभाव करना चाहिए जबकि डीपीओ को सेवाएँ उसी दर पर देनी चाहिए, जो साधारण उपभोक्ता के लिए हैं।
25. होटल और रेस्तरां उद्योग संघों में से एक ने कहा है कि पहले मॉडल को अंगीकार नहीं किया जाना चाहिए, जबकि एक होटल उद्योग संघ ने तीसरे मॉडल के लिए अपनी पसंद जाहिर की है।

विश्लेषण

26. भारत में टीवी चैनलों की डाउनलिकिंग के लिए दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रावधान हैं:—

“5.6 आवेदक कंपनी (प्रसारक), उपग्रह टीवी चैनल सिग्नल रिसेप्शन डीकोडरों को केवल एमएसओ/केबल ऑपरेटरों को, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अधीन पंजीकृत हैं या भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए डीटीएच दिशानिर्देशों के अधीन पंजीकृत किसी डीटीएच ऑपरेटर को या उनके विद्यमान टेलीकॉम लाइसेंस के अधीन विधिवत अनुमत या दूरसंचार विभाग द्वारा अधिकृत किसी इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा प्रदाता को या इस तरह की सेवा प्रदान करने के लिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एचआईटीएस ऑपरेटरों के लिए नीतिगत दिशानिर्देश के अधीन विधिवत अनुमत किसी एचआईटीएस ऑपरेटर को प्रदान करेगा।”

अतः, प्रसारक अपने सिग्नलों को सीधे उपभोक्ताओं, जिनमें वाणिज्यिक उपभोक्ता शामिल हैं, को नहीं दे सकता। प्रसारकों को सिग्नलों की आपूर्ति किसी डीपीओ के माध्यम से करनी होगी। यदि कोई वाणिज्यिक उपभोक्ता टीवी सिग्नलों को उसके क्षेत्र में परिचालन करने वाले किसी भी एमएसओ या उससे सम्बंधित स्थानीय केबल ऑपरेटर/डीटीएच ऑपरेटर/एचआईटीएस आदि ऑपरेटरों से प्राप्त कर सकता है, तो यह बाजार में प्रतिस्पर्धा को भी सुनिश्चित करेगा। तदनुसार, ‘साधारण सब्सक्राइबर’ तथा ‘सब्सक्राइबर’ की परिभाषा को भी उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है।

वाणिज्यिक उपभोक्ताओं का उप-वर्गीकरण

27. परामर्श पत्र में, समान प्रकार से रखे गए समूहों में वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के उप-वर्गीकरण और टैरिफ को उस प्रकार से नियत करने के मुद्दे के बारे में चर्चा की गई और हितधारकों के विचारों की मांग की गई। लगभग सभी हितधारकों का विचार यह था कि किसी भी तरह का ऐसा उप-वर्गीकरण और टैरिफ को उस प्रकार से नियत करना आगे बढ़ने की दिशा में उपयुक्त नहीं हो सकता है।

विश्लेषण

28. वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को टेलीविजन सिग्नलों की पेशकश करने के तरीके के संबंध में टैरिफ प्रावधान तथा उपबंधों के मद्देनजर, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ विहित करने के प्रावधान के प्रयोजनार्थ समान समूहबद्ध करने हेतु, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को उप-श्रेणीबद्ध किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपेक्षित भेद के अनुसार, वाणिज्यिक उपभोक्ता को मुख्यतः दो वर्गों में रखा गया है :- (1) जो अपने आगन्तुकों को सुविधाओं के भाग के रूप में टेलीविजन सेवाओं/कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं, (2) जो उपयुक्त पैरा 21 में यथा-चर्चा की गई पद्धति के माध्यम से इसे प्रभाषित करते हैं।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2014

THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE) SERVICES (FOURTH) (ADDRESSABLE SYSTEMS) TARIFF (FOURTH AMENDMENT) ORDER, 2014

(No. 6 of 2014)

No. 1-19/2014 - B&CS.— In exercise of the powers conferred by sub-clauses (ii), (iii), (iv) and (v) of clause (b) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Government of India, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunications), No.39,—

(a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government by proviso to clause (k) of sub-section (1) of section 2 and clause (d) of sub-section (1) of section 11 of the said Act, and

(b) published under notification No. 39 [S.O. 44 (E) and 45 (E)] dated the 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II- Section 3- Sub-section (ii), —

the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2010 (1 of 2010), namely:-

1. (1) This Order may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff (Fourth Amendment) Order, 2014 (6 of 2014).

(2) This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 3 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2010 (1 of 2010), (hereinafter referred to as the principal Tariff Order),—

(a) after sub-clause (o), the following sub-clause (oa) shall be inserted, namely:—

“(oa) “commercial establishment” means any premises wherein any trade, business or any work in connection with, or incidental or ancillary thereto, is carried on and includes a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), and charitable or other trust, whether registered or not, which carries on any business, trade or work in connection with, or incidental or ancillary thereto, journalistic, printing and publishing establishments, educational, healthcare or other institutions run for private gain, theatres, cinemas, restaurants, eating houses, pubs, bars, residential hotels, malls, airport lounges, clubs or other places of public amusements or entertainment;”

(b) after sub-clause (oa), so substituted, the following sub-clause (oab) shall be inserted, namely:—

“(oab) “commercial subscriber” means any person who receives broadcasting services or cable services at a place indicated by him to a cable operator or multi system operator or direct to home operator or head end in the sky operator or Internet Protocol television service provider, as the case may be, and uses such services for the benefit of his clients, customers, members or any other class or group of persons having access to his commercial establishment;”

(c) for the sub-clause (z), the following sub-clause shall be substituted, namely.—

“(z) “ordinary subscriber” means any subscriber who receives broadcasting services or cable services from multi system operator or cable operator or direct to home operator or Internet Protocol television service provider or head end in the sky operator, as the case may be, and uses the same for his domestic purposes;”

(d) for the sub-clause (ze), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

“(ze) “subscriber” means a person who receives broadcasting services or cable services from a multi system operator or cable operator or direct to home operator or Internet Protocol television service provider or head end in the sky operator at a place indicated by him to the multi system operator or cable operator or direct to home operator or Internet Protocol television service provider or head end in the sky operator, as the case may be, without further transmitting it to any person and includes ordinary subscribers and commercial subscribers, unless specifically excluded;”

3. In clause 6 of the principal Tariff Order, —

(a) the word ‘ordinary’, wherever appearing, shall be deleted;

(b) after sub-clause (4), the following sub-clause and Explanation shall be inserted, namely: —

“(5) If a commercial subscriber charges his customer or any person for a programme of a broadcaster shown within his premises, he shall, before he starts providing such service, enter into agreement with the broadcaster and the broadcaster may charge the commercial subscriber, for such programme, as may be agreed upon between them.

Explanation: For the removal of doubt, it is clarified that any increase in the price of goods or services, being provided by the commercial subscriber during the duration of the telecast of a programme, referred to in the sub-clause (5), shall also be treated as charge for the said programme.”

SUDHIR GUPTA, Secy.

[ADVT III/4/Exty./142/14]

Note.1—The principal Tariff Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section-4 vide notification No. 11-14/2009-B&CS dated the 21st July, 2010 and subsequently amended vide notifications No.1-9/2012 - B&CS dated the 30th April 2012, No. 1-12/2012-B&CS, dated the 20th September, 2013 and No. 1-9/2012 - B&CS, dated the 10th February, 2014.

Note. 2—The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Fourth) (Addressable Systems) Tariff (Fourth Amendment) Order, 2014 (6 of 2014).

Annexure

Explanatory Memorandum

Background

1. The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) was entrusted with the responsibility of regulating ‘broadcasting and cable TV’ services in January, 2004. An interim Tariff Order was issued on 15.01.2004, which provided that the cable charges prevailing on 26.12.2003 shall be the ceilings at the respective levels. Thereafter, following extensive consultations, a detailed Tariff Order was issued on 01.10.2004. This order, while maintaining the sanctity of the ceiling of cable TV charges prevailing on 26.12.2003, also provided a window for introduction of new pay channels and conversion of existing Free-to-Air (FTA) channels to ‘pay channels’ subject to prescribed conditions. The underlying objective of these Tariff orders was to give relief and protection to consumers of broadcasting and cable TV services from frequent hikes in cable TV charges.
2. Subscribers of broadcasting and cable TV services are basically of two kinds. First, there are ordinary subscribers who consume TV services domestically for their own pleasure. The second group comprises commercial subscribers who obtain TV services for the benefit of their clients, customers etc., at their commercial establishment. While issuing the Tariff Orders in 2004, as mentioned above, the Authority, however, did not differentiate between ordinary and commercial subscribers.
3. The matter pertaining to tariffs for commercial subscribers has been under judicial scrutiny since 2005, before the Hon’ble Telecom Disputes Settlement Appellate Tribunal (TDSAT), when Hotels and Restaurants Association (Western India) (HRAWI), a sister association of Federation of Hotel and Restaurant Associations of India (FHRAI), challenged differential tariffs imposed by some broadcasters. The Hon’ble TDSAT disposed of these petitions *vide* its judgment dated 17.01.2006 wherein it concluded that the members of the petitioner associations couldn’t be regarded as subscribers or consumers. It also asked the Authority to consider whether it was necessary or not to fix tariff for commercial cable TV subscribers.
4. As an interim measure, on 07.03.2006, the Authority issued an amendment to the principal Tariff Order of 01.10.2004. This Tariff Amendment Order defined the terms ‘Ordinary cable subscriber’ and ‘Commercial cable subscriber’. In the meanwhile, the aforesaid judgment of the Hon’ble TDSAT was appealed by the Associations of Hotels and Restaurants before the Hon’ble Supreme Court. In an interim order on 19.10.2006, the Hon’ble Supreme Court directed the Authority to carry out the processes for framing the tariff under Section 11 of the TRAI Act, independently and not relying on or on the basis of any observation made by TDSAT. In its final order on 24.11.2006, the Hon’ble Supreme Court confirmed its interim orders and stated that it did not agree with the opinion of the Hon’ble TDSAT that the Authority should also consider whether it is necessary or not to fix tariff for commercial cable TV subscribers.
5. Based on the interim order of the Hon’ble Supreme Court dated 19.10.2006, the Authority issued two Tariff Amendment Orders, on 21.11.2006, applicable to commercial subscribers in non-CAS and CAS areas, respectively. This tariff amendment order categorized commercial subscribers into the following two groups, namely: —
 - (c) A specified category of commercial subscribers comprising—
 - (i) Hotels with rating of 3 stars and above;

- (ii) Heritage hotels (as defined by the Department of Tourism, Government of India);
 - (iii) Any hotel, motel, inn or commercial establishment providing board & lodging and having 50 or more rooms; and
 - (d) All other commercial subscribers (not falling under the specified category of commercial subscribers).
6. The tariff for cable TV services for the specified category of commercial subscribers was to be mutually determined by the parties. However, the tariff for commercial subscribers not falling in the specified categories (coming under the second category) was subject to the same charges as ordinary cable subscribers and thus the ceiling of rates prevailing as on 26.12.2003 was made applicable to them. The tariff amendment order also provided that whenever a commercial cable TV subscriber belonging to either of the two categories uses the programme of a broadcaster for public viewing by fifty or more persons on the occasion of special events at a place registered under the Entertainment Tax Act, the tariff will have to be mutually decided between the parties concerned.
7. These orders too were appealed against in the Hon'ble TDSAT by way of appeals [Appeal No.17(C) of 2006 - East India Hotel Ltd. Vs. TRAI & Ors and Appeal No. 18 (C) of 2006 - The Connaught Prominent Hotels Limited vs. TRAI & Ors.] by the hotels and their associations. The Hon'ble TDSAT passed its judgment on 28.05.2010 in the two appeals filed by the hotels against the tariff amendment orders dated 21.11.2006. The operative portion of the judgment of the Hon'ble TDSAT read:
- "We, therefore, are of the opinion that it is a fit case where the impugned orders are required to be set aside. We direct accordingly. We, however, do not wish to issue any direction with regard to the refund of any amount but we would request the Authority to consider the case of commercial establishments once over again in a broad based manner".*
8. In sum, the sub-classification of commercial consumers into two categories was struck down by the Hon'ble TDSAT. Aggrieved by the TDSAT judgement dated 28.05.2010, M/s. ESPN Software India Pvt. Ltd. filed an appeal (CA No. 6040-41 of 2010 -M/s ESPN Software India Pvt. Ltd. Vs. TRAI and Ors.) in the Supreme Court. The judgment of the Hon'ble Supreme Court, dated 16.04.2014, in this case, directs as follows:
- "..... we direct that for a period of three months, the impugned tariff, which is in force as on today, shall continue. Within the said period, TRAI shall look into the matter de novo, as directed in the impugned judgment, and shall re-determine the tariff after hearing the contentions of all the stake holders...."***
9. Accordingly, as directed by the Hon'ble Supreme Court in its judgment dated 16.04.2014, TRAI initiated a consultation process, as part of a de novo exercise, and issued a Consultation Paper (CP) on 11.06.2014 seeking comments/views of the stakeholders. The CP discussed and raised related consultation issues pertaining to various alternatives for tariff stipulations for the commercial subscribers, manner of offering of TV services to them, the definition of the 'commercial establishment', 'shop' and 'commercial subscriber', and sub-categorization of the commercial subscribers into similarly placed groups. In response to the CP, 24 stakeholders submitted their views/comments to the Authority. Subsequently, to further discuss the issues involved, an Open House Discussion (OHD) was also held at Delhi on 4th July, 2014, wherein 59 stakeholders participated in the discussions.
10. This tariff order is being notified after analyzing all the issues involved and the inputs received from various stakeholders.

Analysis of Issues

Definition of commercial subscribers, commercial establishment and shops

11. Draft definitions of commercial subscriber, commercial establishment and shops were discussed in the CP and views/comments of the stakeholders were solicited.

Stakeholder comments

12. Several broadcasters including the two prominent broadcasters, a broadcasting industry association, a Hotel industry association as well as a couple of cable TV operator associations have broadly agreed with the draft definitions. Some of them have pointed out that the 'profession' appearing in the definition of 'commercial establishments' should be deleted as some court decisions have held that the premises of doctors, lawyers, engineers etc. should not be considered commercial establishments. Some other broadcasters have stated that shops, factories and public viewing areas should be included in the definition of 'commercial establishment'. It was also suggested by a broadcaster that 'publishing' should also be included in the definition of 'commercial establishments'. An association of broadcasters and some other stakeholders from the broadcasters fraternity have

put forth the view that any premise, indoor or outdoor, that is not a domestic premise should be categorized as commercial and commercial subscribers be defined in an all inclusive manner to include all subscribers except residential subscribers.

13. The majority of the distribution platform operators, cable and DTH, as well as a hotel and restaurant industry association are of the view that there is no need to make a distinction between ordinary and commercial subscribers and all subscribers should be treated at par. It has also been suggested to include the concept of commercial purpose and/or commercial exploitation into the definition of commercial establishment. Another industry association has proposed that commercial subscriber should be defined as the one who uses TV signals as its business or commercial activity or part thereof, irrespective of whether TV channels are charged or not from the viewers/audience.

Analysis

14. Taking into account the views of the stakeholders, the definition of 'commercial establishment' has been included and the definition of 'commercial subscriber' has been accordingly amended. This is also in line with the tariff prescription and the manner of offering of television services to the commercial subscribers, which have been discussed in subsequent paragraphs.

Tariff for Commercial subscribers

15. In the CP, the following four alternatives were discussed for prescribing tariff for commercial subscribers, seeking views/comments of the stakeholders:
 - (i) The tariff for commercial subscribers is the same as that for ordinary subscribers.
 - (ii) The tariff for commercial subscribers has a linkage with the tariff for ordinary subscribers.
 - (iii) The tariff for commercial subscribers has no linkage with the tariff for ordinary subscribers but there are some protective measures prescribed to protect all the stakeholders such as mandatory a-la-carte offering, conditions to prevent perverse a-la-carte pricing vis-à-vis bouquet rates etc.
 - (iv) The tariff for commercial subscribers is kept under total forbearance.

Stakeholder comments

16. Hotel industry associations and almost all distribution platform operators (DPOs) have advocated for adoption of the first alternative discussed in the CP i.e. the tariff for commercial subscribers should be same as that prescribed for the ordinary subscribers. To support their view, the main arguments put forth have been - (i) the ultimate consumer/viewer is the same whether the TV services are availed at the domestic premises of the consumer or in a hotel or hospital or any other commercial establishment, (ii) a consumer does not go to such commercial establishment specifically to view TV channels, (iii) there is no extra cost to the broadcaster for production of content and its distribution in both the cases and the content/quality of signal remains the same. Some of them further stated that, in cases where the consumer goes to a commercial establishment specifically to avail TV services and pays for it, the tariff may be different from that for the ordinary subscribers.
17. On the other hand, all broadcasters and their representative bodies are of the view that the fourth alternative, prescribing total forbearance on tariff for commercial subscribers, be adopted. The main arguments presented by them in this regard are – (i) the TV services are basically non-essential services and, therefore, need not be regulated, (ii) in many international markets, differential pricing is done for the commercial subscribers, (iii) commercial subscribers exploit the TV signals for commercial gains, therefore, the broadcasters are entitled to a fair share of the same. In response to a query during the OHD, an Association of broadcasters has indicated that the total revenue of the commercial subscribers that are 'known' to subscribe to television are estimated at 1.5-2.2% of total distribution revenues.
18. A headend in the sky (HITS) operator has suggested for prescription of the second alternative which provides that there should be a certain linkage between the tariff for ordinary and commercial subscribers. A broadcaster and a couple of cable operator associations have expressed their preference for the third alternative. It has also been suggested by a multi system operator (MSO) that a broadcaster should prescribe the retail price of its channels for different categories of commercial subscribers and the revenue share for different stakeholders in the value chain should be determined by TRAI.

Analysis

19. The end consumer, whether at his domestic premises or at any commercial establishment, gets to view the same content with same quality of signals. In both the cases, the cost to the content owner (broadcaster) and the DPO, for supplying the signals, per se, does not vary on account of where the signals are supplied - at the domestic premises or the commercial establishment. Moreover, The Hon'ble Supreme Court in its judgment dated

24.11.2006 in appeal (Civil) 2061 of 2006 Hotel and Restaurants Association and Anr Vs Star India Pvt. Ltd. and Ors has, amongst others, observed as under:

"....The owners of the hotels take TV signals for their customers/ guests. While doing so, they inter alia provide services to their customers. An owner of a hotel provides various amenities to its customers such as beds, meals, fans, television, etc. Making a provision for extending such facilities or amenities to the boarders would not constitute a sale by an owner to a guest. The owners of the hotels take TV signals from the broadcasters in the same manner as they take supply of electrical energy from the licensees. A guest may use an electrical appliance. The same would not constitute the sale of electricity by the hotel to him. For the said purpose, the 'consumer' and 'subscriber' would continue to be the hotel and its management. Similarly, if a television set is provided in all the rooms, as part of the services rendered by the management by way of an amenity, wherefor the guests are not charged separately, the same would not convert the guests staying in a hotel into consumers or subscribers....."

The said judgment further quotes another judgment of the Hon'ble Supreme Court (in The State of Punjab v. M/s. Associated Hotels of India Ltd. [(1972) 1 SCC (472)]) on similar issue, which is reproduced as under:

".... When a traveller, by plane or by steam-ship, purchases his passage-ticket, the transaction is one for his passage from one place to another. If, in the course of carrying out that transaction, the traveller is supplied with drinks or meals or cigarettes, no one would think that the transaction involves separate sales each time any of those things is supplied. The transaction is essentially one of carrying the passenger to his destination and if in performance of the contract of carriage something is supplied to him, such supply is only incidental to that services, not changing either the pattern or the nature of the contract. Similarly, when clothes are given for washing to a laundry, there is a transaction which essentially involves work or service, and if the laundryman stitches a button to a garment which has fallen off, there is no sale of the button or the thread. A number of such cases involving incidental uses of materials can be cited, none of which can be said to involve a sale as part of the main transaction."

20. From the observations of the Hon'ble Supreme Court, cited above, it is clear that provision of TV services in a commercial establishment is only incidental to the service that the commercial establishment is providing to its clients. It cannot be construed as re-distribution or re-sale of TV services. In any case, there is no re-transmission. In sum, the question as to who is the subscriber has been settled through this judgment. It has also been settled by the said judgment that any service rendered to a guest by way of an amenity, wherefor the guests are not charged separately, the same would not constitute as sale of the said service to the guest. Further, this judgment specifically refers to the subject in hand. **Accordingly, the Authority was of the view that in the rates of TV services, there should be no differentiation between an ordinary subscriber and a commercial subscriber i.e. in both the cases, the charges should be the same and on per set top box (STB) basis.** In view of the above, clause 6 of the tariff order has been suitably amended.
21. However, in case, the commercial establishment specifically charges extra to its clients/visitors on account of viewing of channels at its premises, there is a case for broadcasters to have a share in such revenue of the commercial establishment. Therefore, where the commercial establishment is earning extra revenue from its clients specifically on account of providing TV services, the rates should be based on mutual negotiations between the broadcaster and the commercial subscriber. In such cases also, the commercial subscriber would be required to obtain such signals of TV channel through a DPO/cable operator only. Accordingly, sub-clause (5) has been added to clause 6 through this tariff amendment order.

Manner of offering TV channels to the commercial subscribers

22. Three models of offering of TV channels to commercial subscribers were discussed in the CP. The first model envisages that the commercial subscriber enters into agreement with the broadcaster and obtains signals either from the broadcaster itself or a DPO designated by the broadcaster. In the second model, the commercial subscriber is to enter into agreement with the DPO and obtain the signals while DPO and broadcasters have their own mutually agreed arrangements. The third model discussed in the CP is a combination of the first and second models.

Stakeholder Comments

23. Almost all the broadcasters and their representative bodies and agents have stated that only the first model is viable and should be adopted. While suggesting a detailed procedure for implementation of this model they have reasoned that – (a) the second model is prone to commercial subscribers not getting signal because of potential breakdown of negotiations between broadcasters and DPOs and (b) the third model is prone to confusion, as both broadcasters and DPOs would be allowed to provide Reference Interconnect Offers (RIOs).

24. Almost all the DPOs have suggested adoption of second model. A couple of cable TV operator associations have opined that the regulator should fix the MRP based on which the broadcasters and DPOs make the RIO. However, broadcasters should not identify the DPO through which the commercial subscriber should get the signals of the broadcaster. They have also stated that in cases where commercial subscribers have their own headend, the broadcasters can directly negotiate with the commercial subscribers as per RIO. Another cable operator association has stated that the broadcaster and commercial subscribers should negotiate the rates while the DPO should give the services at the same rate as for ordinary subscriber.
25. One of the hotel and restaurant industry associations has stated the first model should not be adopted, while another hotel industry association has expressed its preference for the third model.

Analysis

26. The guideline for downlinking of TV channels in India prescribe as under:

"5.6. The applicant company shall provide Satellite TV Channel signal reception decoders only to MSOs/Cable Operators registered under the Cable Television Networks (Regulation) Act 1995 or to a DTH operator registered under the DTH guidelines issued by Government of India or to an Internet Protocol Television (IPTV) Service Provider duly permitted under their existing Telecom License or authorized by Department of Telecommunications or to a HITS operator duly permitted under the policy guidelines for HITS operators issued by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India to provide such service."

So, the broadcaster cannot supply signals directly to subscribers, including the commercial subscribers. Broadcasters should supply their signals through a DPO. It would also ensure competition in the market if a commercial subscriber can obtain TV signals from any MSO or its linked local cable operator /DTH operator etc. operating in his area. Accordingly, the definitions of 'ordinary subscriber' and 'subscriber' have also been amended suitably.

Sub-categorization of commercial subscribers

27. In the CP, the issue regarding sub-categorization of commercial subscribers into similarly placed groups and fixing the tariff therefor was discussed and views of the stakeholders were sought. Almost all the stakeholders, across all the segments, are of the view that any such sub-categorization and fixing of tariff for such sub-categories may not be the appropriate way forward.

Analysis

28. In view of the tariff prescription and the provisions regarding manner of offering of TV signals to the commercial subscribers, there is no need for sub-categorization of the commercial subscribers into similarly placed groups for the purpose of prescription of tariff dispensation for commercial subscribers. The only distinction required is to place the commercial subscribers into two broad classes – (i) those who offer television services/programmes as part of amenities to their guests and (ii) those who charge for the same in the manner as discussed in para 21 above.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2014

दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (आठवां संशोधन) विनियम, 2014

(2014 का 8)

सं. 6-32/2014-बीएंडसीएस – भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना संख्या 39 के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), (iii) और (iv) और धारा 36 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो—

(ए) उक्त अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) के परंतुक तथा धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(बी) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, के खंड 3 के उप-खंड (ii) में दिनांक 09 जनवरी, 2004 की अधिसूचना सं० 39 (का.आ. 44 (अ) तथा 45(अ)) के तहत प्रकाशित हुई थी,—

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन विनियम, 2004 (2004 का 13) में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :-

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (आठवां संशोधन) विनियम, 2014 (2014 का 8) कहा जाएगा।
- (2) ये आदेश सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन विनियम, 2004 (2004 का 13) (जिसे इसमें आगे मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 में,—
 - (ए) खंड (आईबी) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

“(आईबी) **“वाणिज्यिक प्रतिष्ठान”** से आशय, ऐसा भवन, जहां व्यापार, व्यवसाय और कार्य किए हैं, जो प्रांसगिक अथवा अनुषंगी हो, जिसमें सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21वां) तथा पूर्त अथवा अन्य न्यास चाहे वे पंजीकृत हो अथवा नहीं, जो कोई व्यापार, व्यवसाय अथवा इससे जुड़े अथवा इससे संबंधित कार्य करते हो, जिसमें निजी लाभ के लिए चलाए जा रहे पत्रकारिता तथा मुद्रण प्रतिष्ठान, शिक्षण, स्वास्थ्य परिचर्या अथवा अन्य संस्थान, थियेटर, सिनेमा, खानपान गृह, पब-बार, आवासीय होटल, मॉल, विमानपत्तन लाऊंज, क्लब अथवा सार्वजनिक मनोरंजन अथवा आमोद-प्रमोद के अन्य स्थान शामिल हैं, से है;”
 - (बी) प्रतिस्थापित किए गए खंड (आईबी) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

“(आईसी) **“वाणिज्यिक सब्सक्राइबर”** से आशय, कोई भी व्यक्ति, जो किसी केबल ऑपरेटर अथवा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा डायरेक्ट-टु-होम ऑपरेटर अथवा हेडएण्ड-इन-द-स्काई ऑपरेटर अथवा इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, को इंगित किए गए स्थान पर प्रसारण सेवाएं या केबल सेवाएं प्राप्त करता हो और ऐसी सेवाओं को अपने ग्राहकों, उपभोक्ताओं, सदस्य अथवा अन्य व्यक्तियों के वर्ग अथवा समूह, जिनकी उसके वाणिज्यिक प्रतिष्ठान तक पहुंच है, के लाभ के लिए उपयोग करता हो, से है;”
 - (सी) खंड (एमए) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

“(एमए) **“साधारण सब्सक्राइबर”** से आशय, कोई भी सब्सक्राइबर, जो एक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा केबल ऑपरेटर अथवा डायरेक्ट-टु-होम ऑपरेटर अथवा इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा प्रदाता अथवा हेडएण्ड-इन-द-स्काई ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, से प्रसारण सेवाएं या केबल सेवाएं प्राप्त करता है तथा उसका प्रयोग अपने घरेलू उपयोग के लिए करता है, से है;”
 - (डी) “उप-खंड (जेडए) के लिए, निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

“(जेडए) **“सब्सक्राइबर”** से आशय, एक व्यक्ति, जो एक मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा केबल ऑपरेटर अथवा डायरेक्ट-टु-होम ऑपरेटर अथवा इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा प्रदाता अथवा हेडएण्ड-इन-द-स्काई ऑपरेटर से उसके द्वारा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा केबल ऑपरेटर अथवा डायरेक्ट-टु-होम ऑपरेटर अथवा इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा प्रदाता अथवा हेडएण्ड-इन-द-स्काई ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, को इंगित किए गए स्थान पर, उसे आगे किसी भी व्यक्ति को संचारित (ट्रांसमिट) किए बिना और जिसमें साधारण सब्सक्राइबर एवं वाणिज्यिक सब्सक्राइबर शामिल हैं, जिन्हें जब तक विशेष रूप से बाहर न रखा गया हो, प्रसारण सेवाएं या केबल सेवाएं प्राप्त करता है, से है;”
3. मूल विनियम के विनियम-13.2ए.1 में से, दूसरे परंतुक तथा अंत में वर्णित स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।

सुधीर गुप्ता, सचिव
[विज्ञापन III / 4 / असाधारण / 142 / 14]

टिप्पणी:—1 : मूल विनियमों को 10 दिसंबर, 2004 की अधिसूचना संख्या 8-26/2004-बीएण्डसीएस के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया तथा इन्हें बाद में 03 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 3-57/2005-बीएण्डसीएस, 24 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या 11-13/2006-बीएण्डसीएस, 04 सितंबर, 2006 की अधिसूचना संख्या 6-4/2006-बीएण्डसीएस, 03 सितंबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 4-54/2007-बीएण्डसीएस, 17 मार्च, 2009 की अधिसूचना संख्या 3-21/2009-बीएण्डसीएस, 30 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या 6-7/2010-बीएण्डसीएस तथा 10 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या 6-11/2014-बीएण्डसीएस के माध्यम से संशोधित किया गया ।

टिप्पणी:—2 : व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (आठवां संशोधन) विनियम, 2014 (2014 का 8) के उद्देश्यों एवं कारणों को स्पष्ट किया गया है ।

अनुलग्नक

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पृष्ठभूमि

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को जनवरी 2004 में 'प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं' को विनियमित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक अंतरिम टैरिफ आदेश को 15.01.2004 को जारी किया गया था, जिसमें प्रावधान किया गया था कि 26.12.2003 को विद्यमान केबल शुल्क सम्बंधित स्तरों पर ऊपरी सीमा होंगे। इसके बाद, व्यापक विचार विमर्श के बाद, एक विस्तृत टैरिफ आदेश 01.10.2004 को जारी किया गया था। इस आदेश ने, 26.12.2003 पर प्रचलित केबल टीवी के शुल्कों की ऊपरी सीमा की वैधता को बनाए रखते हुए निर्धारित शर्तों के अधीन, नए पे-चैनलों के प्रारम्भ और विद्यमान फ्री-टु-एयर (एफटीए) चैनलों के 'पे-चैनलों' में रूपांतरण के लिए प्रावधान भी किया था। इन टैरिफ आदेशों का अन्तर्निहित प्रयोजन केबल टीवी शुल्कों में बारम्बार बढ़ोतरी से प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं के उपभोक्ताओं को राहत और संरक्षण देना था।
2. प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं के सब्सक्राइबर(उपभोक्ता) मूल रूप से दो प्रकार के हैं – एक तरफ साधारण उपभोक्ता हैं, जो टीवी सेवाओं का उपभोग घरेलू रूप से और अपने आनन्द के लिए करते हैं, जबकि दूसरी तरफ वाणिज्यिक उपभोक्ता हैं जो उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर टीवी सेवाओं को उनके उपभोक्ताओं आदि के लाभ के लिए प्राप्त करते हैं। 2004 में टैरिफ आदेशों को जारी करते समय, जैसा ऊपर उल्लिखित है, प्राधिकरण ने, फिर भी, साधारण और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के बीच भेद नहीं किया था।
3. वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ का मामला 2005 से न्यायिक जांच के अधीन है, जब होटल एवं रेस्टोरेंट संघ (पश्चिमी भारत) (एचआरएडब्ल्यूआई), जो भारतीय होटल एवं रेस्टोरेंट संघ महासंघ (एफएचआरएआई) की एक सहयोगी संगठन है, ने कुछ प्रसारकों द्वारा थोपे गए अंतरीय टैरिफों को माननीय टेलीकॉम विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के समक्ष चुनौती दी थी। माननीय टीडीसैट ने याचिकाओं को अपने निर्णय दिनांकित 17.01.2006 के माध्यम से निपटारा था, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला था कि याचिकाकर्ता संघों के उपभोक्ताओं को सदस्यों या उपभोक्ताओं के रूप में नहीं माना जा सकता है। प्राधिकरण ने इस पर विचार करने के लिए भी कहा था कि क्या वाणिज्यिक केबल टीवी उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ नियत करना आवश्यक था या नहीं।
4. एक अंतरिम उपाय के रूप में, 07.03.2006 को, प्राधिकरण ने 01.10.2004 के प्रमुख टैरिफ आदेश का एक संशोधन जारी किया था। इस टैरिफ संशोधन आदेश ने शब्दों 'साधारण केबल सब्सक्राइबर' और 'वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर' को परिभाषित किया था। इस बीच, माननीय टीडीसैट के उपरोक्त निर्णय पर होटल और रेस्तरां के संघों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील की गई थी। 19.10.2006 पर एक अंतरिम आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्राधिकरण को ट्राई अधिनियम की धारा 11 के अधीन टैरिफ तैयार करने के लिए प्रक्रियाओं को, स्वतंत्र रूप से और टीडीसैट द्वारा किए गए किसी भी अवलोकन पर न निर्भर करते हुए और न ही उसके आधार पर, करने का निर्देश दिया था। 24.11.2006 को अपने अंतिम आदेश में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेशों की पुष्टि की और कहा कि वो माननीय टीडीसैट की राय से सहमत नहीं थे कि प्राधिकरण को इस पर भी विचार करना चाहिए कि क्या वाणिज्यिक केबल टीवी उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ नियत करना आवश्यक है या नहीं।
5. प्राधिकरण ने इस बीच 21.11.2006 को, माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांकित 19.10.2006 पर आधारित, दो टैरिफ संशोधन आदेशों को जारी किया था, जो क्रमशः, गैर-सीएस और सीएस क्षेत्रों में वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर लागू हैं। इस टैरिफ संशोधन आदेश ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को निम्नलिखित दो समूहों में वर्गीकृत किया, अर्थात्:—

(क) वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की एक विशिष्टीकृत श्रेणी जो निम्नलिखित से मिलकर बनी है:—

- (i) 3 स्टार और उच्चतर रेटिंग वाले होटल;
- (ii) हेरिटेज होटल (जैसे कि पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा परिभाषित हैं);

- (iii) आवास व भोजन उपलब्ध कराने वाला और 50 या अधिक कमरे होने वाला कोई भी होटल, मोटल, सराय (इन्) या व्यावसायिक प्रतिष्ठान; और

(ख) अन्य सभी वाणिज्यिक उपभोक्ता (वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की विशिष्टीकृत श्रेणी के अंतर्गत न आने वाले)।

6. वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की विशिष्टीकृत श्रेणी के लिए केबल टीवी सेवाओं के टैरिफ को दलों द्वारा पारस्परिक रूप से निर्धारित किए जाने के लिए रखा गया था। विशिष्टीकृत श्रेणियों में न आने वाले और इस तरह दूसरी श्रेणी के अधीन आने वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को उसी शुल्क के अधीन रखा गया था, जैसा साधारण केबल उपभोक्ताओं के लिए था और इस प्रकार 26.12.2003 को प्रचलित दरों की ऊपरी सीमा को उन पर लागू किया गया था। टैरिफ संशोधन आदेश ने यह प्रावधान भी किया था कि जब कभी भी दो श्रेणियों में से किसी एक से सम्बन्धित कोई वाणिज्यिक केबल टीवी उपभोक्ता किसी प्रसारक के कार्यक्रम का उपयोग मनोरंजन कर अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी स्थान पर विशेष आयोजनों के अवसर पर पचास या अधिक व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक रूप से देखने के लिए करता है, तो टैरिफ का निर्णय सम्बन्धित पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से अवश्य करना होगा।

7. इन आदेशों के विरुद्ध भी होटल और उनके संगठनों द्वारा अपीलों (अपील संख्या 2006 की 17(सी) – ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड बनाम ट्राई एवं अन्य और अपील संख्या 2006 की 18(सी) – कनॉट प्रॉमिनेन्ट होटल्स लिमिटेड बनाम ट्राई एवं अन्य) के माध्यम से माननीय टीडीसैट में अपील की गई थी। टैरिफ संशोधन आदेशों दिनांकित 21.11.2006 के विरुद्ध होटलों द्वारा दायर की गई दो अपीलों में माननीय टीडीसैट ने अपना निर्णय 28.05.2010 को पारित किया था। माननीय टीडीसैट के निर्णय के परिचालनात्मक भाग में लिखा है:-

“हमारी राय, इसलिए, यह है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहाँ खण्डित किए गए आदेशों को रद्द करने की आवश्यकता है। हम तदनुसार निर्देश देते हैं। हम, फिर भी, किसी भी राशि की धन-वापसी के सम्बन्ध में कोई भी निर्देश जारी करना नहीं चाहते हैं परन्तु हम प्राधिकरण से “एक व्यापक ढंग से एक बार फिर से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मामले पर विचार करने का अनुरोध करेंगे”।

8. कुल मिलाकर, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के दो श्रेणियों में उप-वर्गीकरण को माननीय टीडीसैट द्वारा हटा दिया गया था। टीडीसैट के निर्णय दिनांकित 28.05.2010 से व्यथित, मैसर्स ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक अपील (सीए संख्या 2010 की 6040-41 – मैसर्स ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम ट्राई और अन्य) सुप्रीम कोर्ट में दायर की। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांकित 16.04.2014, इस मामले में, निम्नानुसार निर्देशित करता है:-

“... हम निर्देशित करते हैं कि खण्डित किया गया टैरिफ, जो आज की स्थिति के अनुसार प्रभावी है, तीन महीने की अवधि के लिए जारी रहेगा। कथित अवधि के भीतर, ट्राई, मामले पर नए सिरे से नज़र डालेगा, जैसा कि खण्डित किए गए निर्णय में निर्देशित किया गया है, और सभी हितधारकों के दावों को सुनने के बाद टैरिफ फिर से तय करेगा... .”

9. तदनुसार, जैसा कि उनके निर्णय दिनांकित 16.04.2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया था, ट्राई ने एक परामर्श प्रक्रिया शुरू की, एक नए सिरे से अभ्यास के भाग के रूप में, और हितधारकों की टिप्पणियों/ विचारों की मांग करते हुए, 11.06.2014 को एक परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श पत्र ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ शर्तों के लिए विभिन्न विकल्पों से सम्बन्धित परामर्श मुद्दों, उन्हें टीवी सेवाओं की पेशकश करने का तरीका, ‘व्यावसायिक प्रतिष्ठान’, ‘दुकान’ और ‘वाणिज्यिक उपभोक्ता’ की परिभाषा, और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं का समान रूप से रखे गए समूहों में उप-वर्गीकरण, पर चर्चा की और परामर्श के लिए उठाया। परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में, 24 हितधारकों ने अपने विचार/ टिप्पणियां, प्राधिकरण को प्रस्तुत कीं। बाद में, सम्बन्धित मुद्दों पर आगे चर्चा करने के लिए, एक ओपन हाउस परिचर्चा (ओएचडी) भी 4 जुलाई 2014 को दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें 59 हितधारकों ने विचार-विमर्श में भाग लिया।

10. इस अंतःसंयोजन विनियम को, सभी सम्मिलित मुद्दों और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों के विश्लेषण करने के बाद अधिसूचित किया जा रहा है।

मुद्दों का विश्लेषण

वाणिज्यिक उपभोक्ताओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानों की परिभाषा

11. वाणिज्यिक उपभोक्ता, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानों की मसौदा परिभाषाओं की चर्चा परामर्श पत्र में की गई और हितधारकों से विचार/टिप्पणियां मांगी गईं।

हितधारकों की टिप्पणियाँ

12. दो प्रमुख प्रसारकों सहित कई प्रसारक एक प्रसारण उद्योग संघ, एक होटल उद्योग संघ और साथ ही कुछ एक केबल टीवी ऑपरेटर संघ मसौदा परिभाषा के साथ मोटे तौर पर सहमत हुए। उनमें से कुछ कुछ ने इंगित किया कि 'वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों' की परिभाषा में प्रकट होने वाले 'पेशे' को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि कुछ अदालती निर्णयों ने माना है डॉक्टरों, वकीलों, इंजीनियरों आदि के परिसरों को व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं माना जाना चाहिए। कुछ अन्य प्रसारकों ने कहा है कि दुकानों, कारखानों और सार्वजनिक देखने के क्षेत्रों को 'व्यावसायिक प्रतिष्ठान' की परिभाषा में सम्मिलित किया जाना चाहिए। एक प्रसारक द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि "वाणिज्यिक प्रतिष्ठान" की परिभाषा में "प्रकाशन" को भी शामिल किया जाए। प्रसारकों के एक संघ और प्रसारकों की बिरादरी से प्रसारकों कुछ अन्य हितधारकों ने इस विचार को आगे बढ़ाया है कि किसी भी परिसर, चाहे घर के अंदर हो या बाहर हो, जो कोई घरेलू परिसर नहीं है, को व्यावसायिक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को, आवासीय उपभोक्ताओं को छोड़कर, सभी उपभोक्ताओं को सम्मिलित करने के लिए समावेशी तरीके से परिभाषित किया जाए।
13. अधिकांश वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों, केबल और डीटीएच और साथ ही होटल और रेस्तरां उद्योग के एक संघ का विचार है कि साधारण और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बीच कोई अंतर करने की कोई आवश्यकता नहीं है और सभी उपभोक्ताओं को बराबर माना जाना चाहिए। वाणिज्यिक प्रयोजन और/ या वाणिज्यिक दोहन की अवधारणा को व्यावसायिक प्रतिष्ठान की परिभाषा में सम्मिलित करने का सुझाव भी दिया गया है। एक अन्य उद्योग संघ ने प्रस्तावित किया है कि वाणिज्यिक उपभोक्ता को किसी ऐसे एक के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, जो टीवी सिग्नलों का उपयोग उसके व्यापार या वाणिज्यिक गतिविधि या उसके भाग के रूप में करता है, इससे अंतर पड़े बिना कि क्या टीवी चैनलों का शुल्क दर्शकों/श्रोताओं पर लगाया है या नहीं।

विश्लेषण

14. हितधारकों के विचारों को मददे नजर रखकर, 'व्यावसायिक प्रतिष्ठान' की परिभाषा को सम्मिलित किया गया है और 'वाणिज्यिक सब्सक्राइबर' की परिभाषा को तदनुसार संशोधित किया गया है। यह वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ प्रावधानों और उन्हें टेलीविजन सेवाओं की पेशकश करने के तरीके के अनुरूप है, जिनकी चर्चा अगले पैराग्राफों में की गई है।

वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ

15. परामर्श पत्र में, हितधारकों के विचारों/टिप्पणियों की मांग करते हुए, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ विहित करने के लिए निम्न चार विकल्पों पर विचार विमर्श किया गया:—

- (1) वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ साधारण उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ के समान है।
- (2) वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ की साधारण उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ के साथ एक सम्बंध है।
- (3) वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ की साधारण उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ के साथ कोई सम्बंध नहीं है परन्तु सभी हितधारकों की संरक्षा करने के लिए निर्धारित किए गए कुछ सुरक्षा उपाय हैं जैसे कि अनिवार्य अ-ला-कार्टे पेशकश, चैनल-समूह के दरों के साथ-साथ विकृत अ-ला-कार्टे मूल्य निर्धारण को रोकने के लिए शर्तें आदि
- (4) वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ को सम्पूर्ण बाजार की शक्तियों के अधीन रखा गया है।

हितधारकों की टिप्पणियाँ

16. होटल उद्योग के संघों और लगभग सभी वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) ने परामर्श पत्र में चर्चा किए गए पहले विकल्प को अंगीकार करने के लिए वकालत की है अर्थात् वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ साधारण उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित टैरिफ के समान होना चाहिए। उनके दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए, मुख्य रूप से निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं— (i) अंतिम उपभोक्ता/दर्शक एक ही है चाहे टीवी सेवाओं का लाभ उपभोक्ता के घरेलू परिसर में उठाया जाता है या किसी होटल या अस्पताल या किसी भी अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में, (ii) कोई उपभोक्ता इस तरह के वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में विशेष रूप से टीवी चैनलों को देखने के लिए नहीं जाता है (iii) दोनों मामलों में विषय-वस्तु के उत्पादन और इसके वितरण के लिए प्रसारक के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है और साथ ही सिग्नल की विषय-वस्तु/गुणवत्ता भी समान रहती है। उनमें से कुछ ने आगे कहा कि, ऐसे मामलों में, जहां उपभोक्ता किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में विशेष रूप से टीवी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जाता है और इसके लिए भुगतान करता है, तो उनके लिए टैरिफ साधारण उपभोक्ताओं के टैरिफ से अलग हो सकता है।
17. जबकि दूसरी तरफ, सभी प्रसारक और उनके प्रतिनिधि निकाय यह विचार रखते हैं कि चौथे विकल्प, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ को बाजार की शक्तियों पर छोड़ने, को अंगीकार किया जाए। उनके द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्तुत मुख्य तर्क हैं — (i) टीवी सेवाएँ मूल रूप से गैर-ज़रूरी सेवाएँ हैं और इसलिए, इन्हें विनियमित किए जाने की आवश्यकता नहीं है, (ii) कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए अंतरीय

मूल्य निर्धारण किया जाता है, (iii) वाणिज्यिक उपभोक्ता वाणिज्यिक लाभ के लिए टीवी सिग्नलों का दोहन करते हैं, इसलिए, प्रसारक उस लाभ के एक उचित भाग के लिए अधिकृत हैं। ओएचडी के दौरान एक प्रश्न के प्रत्युत्तर में, प्रसारकों के एक संघ ने दर्शाया है कि ऐसे वाणिज्यिक उपभोक्ताओं जिनके बारे में टेलीविजन की सदस्यता लेना 'ज्ञात' है, के कुल राजस्व का कुल वितरण राजस्व का 1.5-2.2 प्रतिशत होने का अनुमान है।

18. एक एचआईटीएस ऑपरेटर ने दूसरे विकल्प को निर्धारित करने का सुझाव दिया, जो यह प्रावधान करता है कि साधारण और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ के बीच कुछ सम्बंध होना चाहिए। एक प्रसारक और कुछ एक केबल ऑपरेटर संघों ने तीसरे विकल्प के लिए उनकी वरीयता व्यक्त की है। एक एमएसओ द्वारा यह सुझाव भी दिया गया है कि प्रसारक को वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की अलग श्रेणी के लिए उनके चैनलों की खुदरा मूल्य को निर्धारित करना चाहिए और मूल्य श्रृंखला में विभिन्न हितधारकों के लिए राजस्व के अंश को ट्राई द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

विश्लेषण

19. अंतिम उपभोक्ता, चाहे उसके घरेलू परिसरों में या किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर, सिग्नलों की उसी गुणवत्ता के साथ उसी विषय-वस्तु को देख पाता है। दोनों ही मामलों में, विषय-वस्तु के स्वामी (प्रसारक) और डीपीओ के लिए लागत, सिग्नलों की आपूर्ति करने के लिए, सहज रूप से, इस तथ्य के कारण से बदलती नहीं है कि सिग्नलों की आपूर्ति घरेलू परिसरों या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में की जाती है। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपील (सिविल) 2006 का 2061 होटल और रेस्टोरेंट संघ और एएनआर बनाम स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य में अपने निर्णय दिनांकित 24.11.2006 में, दूसरों के बीच, निम्नानुसार अवलोकन किया था:-

"... होटलों के स्वामी उनके उपभोक्ताओं/अतिथियों के लिए टीवी सिग्नलों को लेते हैं। ऐसा करते समय, वे अन्य बातों के साथ उनके उपभोक्ताओं को सेवाएँ प्रदान करते हैं। किसी होटल का स्वामी अपने उपभोक्ताओं को विभिन्न सुख-साधनों, जैसे कि बिस्तर, भोजन, पंखे, टेलीविजन, आदि प्रदान करता है। इस तरह की सुविधा या सुख-साधनों का विस्तार, रहने वालों के लिए, करने के लिए कोई प्रावधान करना किसी स्वामी द्वारा किसी अतिथि के लिए एक बिक्री का गठन नहीं करेगा। होटल के स्वामी उसी तरीके से प्रसारकों से टीवी सिग्नलों को लेते हैं, जैसे वे लाइसेंसधारियों से विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति लेते हैं। कोई अतिथि बिजली के किसी उपकरण का उपयोग कर सकता है। यह होटल द्वारा उसे बिजली की बिक्री का गठन नहीं करेगा। कथित प्रयोजन के लिए, 'उपभोक्ता' और 'उपभोक्ता' होटल और उसका प्रबंधन होना जारी रहेंगे। इसी प्रकार, यदि कोई टेलीविजन सेट सभी कमरों में प्रदान किया जाता है, एक सुख-साधन के मार्ग से प्रबंधन द्वारा दी गई सेवाओं के भाग के रूप में, जिसके लिए अतिथियों पर अलग से शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो वह किसी होटल में रहने वाले अतिथियों को ग्राहकों या उपभोक्ताओं में परिवर्तित नहीं करेगा...."

कथित निर्णय इसी तरह के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय के एक अन्य निर्णय (पंजाब राज्य बनाम मैसर्स एसोसिएटेड होटल ऑफ इंडिया लिमिटेड [(1972) 1 एससीसी (472)] को आगे उद्धरित करता है, जो नीचे पुनः उद्धरित किया गया है:-

"... जब कोई यात्री, विमान से या भाप के जहाज से, अपने यात्रा-टिकट को खरीदता है तो लेन-देन एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसकी यात्रा के लिए एक है। यदि, उस लेन-देन को करने के दौरान, यात्री को पेयों या भोजनों या सिगरेटों की आपूर्ति की जाती है, तो कोई भी नहीं सोचेगा कि लेन-देन में अलग बिक्रियाँ सम्मिलित हैं, जब हर बार उनमें से किसी भी चीज की आपूर्ति की जाती है। लेन-देन अनिवार्य रूप से यात्री को उसके गंतव्य तक ले जाने का एक है और यदि ले जाने के अनुबंध के प्रदर्शन में उसे किसी वस्तु की आपूर्ति की जाती है, तो इस तरह की आपूर्ति उन सेवाओं के लिए केवल आकस्मिक है, यह अनुबंध के स्वरूप या फिर प्रकृति को बदलती नहीं है। इसी प्रकार से, जब कपड़ों को किसी लॉण्ड्री को धोने के लिए दिया जाता है, तो वहाँ एक लेन-देन है, जिसमें काम या सेवा अनिवार्य रूप से सम्मिलित है, और यदि लॉण्ड्रीवाला किसी पोशाक का कोई बटन टांक देता है, जो गिर गया है, तो बटन या धागे की कोई बिक्री नहीं है। विषय-वस्तु के आकस्मिक उपयोगों को सम्मिलित करने वाले इस तरह के कई मामलों, को उद्धृत किया जा सकता है जिनमें से किसी को भी मुख्य लेन-देन के भाग के रूप में किसी बिक्री को सम्मिलित करना नहीं कहा जा सकता है।"

20. माननीय उच्चतम न्यायालय की ऊपर की गई टिप्पणियों से, यह स्पष्ट है कि किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में टीवी सेवाओं का वह प्रावधान सेवा के लिए केवल आकस्मिक है, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने उपभोक्ताओं को प्रदान कर रहा है। इसे टीवी सेवाओं के किसी पुनर्वितरण या पुनर्विक्री के अर्थ में नहीं बताया जा सकता है। कुल मिलाकर उपभोक्ता कौन है, इस निर्णय के मामले से इसका निपटान कर दिया गया है। उक्त निर्णय के माध्यम से इस बात का भी निपटान कर दिया गया है कि सुविधा के माध्यम से किसी आगन्तुक को प्रदान की गई सेवा, जहाँ आगन्तुक से इसके लिए अलग से कोई शुल्क नहीं वसूला जाता है, उसे आगन्तुक को सेवा की बिक्री नहीं समझा जाएगा। आगे, यह निर्णय विचाराधीन विषय से सीधे संबंधित है। तदनुसार, प्राधिकरण का यह विचार है कि टीवी सेवाओं, जो कि एनालॉग प्रणाली में प्रति टीवी सेट तथा डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों के मामले में प्रति सेट टॉप बाक्स (एसटीबी) हैं, की दरों को लेकर साधारण उपभोक्ता या वाणिज्यिक उपभोक्ता के बीच कोई अन्तरीकरण नहीं होना

चाहिए, अर्थात् दोनों ही मामलों में, दरों को समान होना चाहिए और वह प्रति टीवी सेट(एनालॉग प्रणालियों में) तथा एसटीबी (डिजिटल एड्रैसेबल प्रणालियों में) के आधार पर होना चाहिए।

21. फिर भी, ऐसे मामले में जब, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान उसके परिसरों में चैनलों को देखने के लिए अपने उपभोक्ताओं/आगंतुकों पर विशेष रूप से अतिरिक्त शुल्क लगाता है, तो प्रसारकों के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठान के इस तरह के राजस्व में किसी अंश के लिए एक मामला है। इसलिए, जहाँ वाणिज्यिक प्रतिष्ठान विशेष रूप से टीवी सेवाएँ प्रदान करने के लिए अपने ग्राहकों से अतिरिक्त राजस्व अर्जित कर रहा है, दरों को प्रसारक और वाणिज्यिक उपभोक्ता के बीच आपसी मोलभावों पर आधारित होना चाहिए। ऐसे मामलों में भी, वाणिज्यिक उपभोक्ता को केवल किसी डीपीओ/केबल ऑपरेटर के माध्यम से टीवी चैनल के इस तरह के सिग्नलों को प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए एड्रैसेबल तथा गैर-एड्रैसेबल प्रणालियों, दोनों के लिए लागू टैरिफ आदेशों में उपयुक्त रूप से संशोधन किया गया है।

वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टीवी चैनलों की पेशकश करने का तरीका

22. वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को टीवी चैनलों की पेशकश करने के तीन मॉडलों की चर्चा परामर्श पत्र में की गई थी। प्रथम मॉडल में यह परिकल्पना की गई है कि वाणिज्यिक उपभोक्ता, प्रसारक के साथ करार कर स्वयं प्रसारक अथवा प्रसारक द्वारा विनिर्दिष्ट डीपीओ से सिग्नल प्राप्त करें। दूसरे मॉडल में, वाणिज्यिक उपभोक्ता, डीपीओ के साथ करार कर सिग्नल प्राप्त करेंगे। जबकि डीपीओ तथा प्रसारकों की आपस में सहमतिपूर्ण व्यवस्था होगी। परामर्श पत्र में चर्चा किया गया तीसरा मॉडल, पहले तथा दूसरे मॉडल का संयोजन है।

हितधारकों की टिप्पणियाँ

23. लगभग सभी प्रसारकों और उनके प्रतिनिधि निकायों और एजेंटों ने कहा है कि केवल मॉडल (i) व्यवहार्य है और इसे अंगीकार किया जाना चाहिए। पहले मॉडल के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया का सुझाव देते हुए, उन्होंने तर्क दिया है कि – (क) दूसरा मॉडल वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को सिग्नल नहीं मिलने के लिए प्रवृत्त है, यदि प्रसारकों और डीपीओ के बीच मोलभाव नहीं हो पाया और (ख) तीसरा मॉडल भ्रम के लिए प्रवृत्त है क्योंकि प्रसारकों और डीपीओ, दोनों को संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ) को प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी।
24. लगभग सभी डीपीओ ने दूसरे मॉडल को अंगीकार करने का सुझाव दिया है। कुछ एक केबल टीवी ऑपरेटर संघों ने विचार व्यक्त किया है कि विनियामक को अधिकतम खुदरा मूल्य नियत करना चाहिए, जिसके आधार पर प्रसारकों और डीपीओ आरआईओ बनाएँ। फिर भी, प्रसारकों को डीपीओ की पहचान नहीं करनी चाहिए, जिसके माध्यम से वाणिज्यिक उपभोक्ता को प्रसारक के सिग्नल मिलने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में जहाँ वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के पास अपने स्वयं के हेडएण्ड हैं, प्रसारक आरआईओ के अनुसार वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के साथ सीधे मोलभाव कर सकते हैं। एक अन्य केबल ऑपरेटर संघ ने कहा है कि प्रसारक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को दरों का मोलभाव करना चाहिए जबकि डीपीओ को सेवाएँ उसी दर पर देनी चाहिए, जो साधारण उपभोक्ता के लिए है।
25. होटल और रेस्तरां उद्योग संघों में से एक ने कहा है कि पहले मॉडल को अंगीकार नहीं किया जाना चाहिए, जबकि एक होटल उद्योग संघ ने तीसरे मॉडल के लिए अपनी पसंद जाहिर की है।

विश्लेषण

26. भारत में टीवी चैनलों की डाउनलिकिंग के लिए दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

“5.6 आवेदक कंपनी (प्रसारक), उपग्रह टीवी चैनल सिग्नल रिसेप्शन डीकोडरों को केवल एमएसओ/केबल ऑपरेटरों को, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अधीन पंजीकृत हैं या भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए डीटीएच दिशानिर्देशों के अधीन पंजीकृत किसी डीटीएच ऑपरेटर को या उनके विद्यमान टेलीकॉम लाइसेंस के अधीन विधिवत अनुमत या दूरसंचार विभाग द्वारा अधिकृत किसी इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवा प्रदाता को या इस तरह की सेवा प्रदान करने के लिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एचआईटीएस ऑपरेटरों के लिए नीतिगत दिशानिर्देश के अधीन विधिवत अनुमत किसी एचआईटीएस ऑपरेटर को प्रदान करेगा।”

अतः, प्रसारक अपने सिग्नलों को सीधे उपभोक्ताओं, जिनमें वाणिज्यिक उपभोक्ता शामिल हैं, को नहीं दे सकता। प्रसारकों को सिग्नलों की आपूर्ति किसी डीपीओ के माध्यम से करनी होगी। यदि कोई वाणिज्यिक उपभोक्ता टीवी सिग्नलों को उसके क्षेत्र में परिचालन करने वाले किसी भी एमएसओ या उससे सम्बंधित स्थानीय केबल ऑपरेटर/डीटीएच ऑपरेटर/एचआईटीएस आदि ऑपरेटरों से प्राप्त कर सकता है, तो यह बाजार में प्रतिस्पर्धा को भी सुनिश्चित करेगा। तदनुसार, “साधारण सब्सक्राइबर” तथा “सब्सक्राइबर” की परिभाषा को भी उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है।

वाणिज्यिक उपभोक्ताओं का उप-वर्गीकरण

27. परामर्श पत्र में, समान प्रकार से रखे गए समूहों में वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के उप-वर्गीकरण और टैरिफ़ को उस प्रकार से नियत करने के मुद्दे के बारे में चर्चा की गई और हितधारकों के विचारों की मांग की गई। लगभग सभी हितधारकों का विचार यह था कि किसी भी तरह का ऐसा उप-वर्गीकरण और टैरिफ़ को उस प्रकार से नियत करना आगे बढ़ने की दिशा में उपयुक्त नहीं हो सकता है।

विश्लेषण

28. वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को टेलीविजन सिग्नलों की पेशकश करने के तरीके के संबंध में टैरिफ़ प्रावधान तथा उपबंधों के मद्देनजर, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ़ विहित करने के प्रावधान के प्रयोजनार्थ समान समूहबद्ध करने हेतु, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को उप-श्रेणीबद्ध किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपेक्षित भेद के अनुसार, वाणिज्यिक उपभोक्ता को मुख्यतः दो वर्गों में रखा गया है :- (1) जो अपने आगन्तुकों को सुविधाओं के भाग के रूप में टेलीविजन सेवाओं/कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं, (2) जो उपर्युक्त पैरा 21 में यथा-चर्चा की गई पद्धति के माध्यम से इसे प्रभारित करते हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, विनियम 13.2ए.1 को पर्याप्त रूप से संशोधित किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2014

**THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE SERVICES) INTERCONNECTION
(EIGHTH AMENDMENT) REGULATION, 2014**

(No. 8 of 2014)

No. 6-32/2014 - B&CS.-- In exercise of the powers conferred by Section 36, and by sub-clauses (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Government of India, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunication) No.39,—

- (a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government by proviso to clause (k) of sub-section (1) of section 2 and clause (d) of sub-section (1) of section 11 of the said Act, and
- (b) published under notification No. 39 [S.O. 44 (E) and S.O. 45 (E)] dated the 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), —

the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation, 2004 (13 of 2004), namely:—

1. (1) These regulations may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Eighth Amendment) Regulation, 2014 (8 of 2014).
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In regulation 2 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation, 2004 (13 of 2004), (hereinafter referred to as the principal regulation), —

(a) for clause (ib), the following clause shall be substituted, namely: —

“(ib) “**commercial establishment**” means any premises wherein any trade, business or any work in connection with, or incidental or ancillary thereto, is carried on and includes a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), and charitable or other trust, whether registered or not, which carries on any business, trade or work in connection with, or incidental or ancillary thereto, journalistic, printing and publishing establishments, educational, healthcare or other institutions run for private gain, theatres, cinemas, restaurants, eating houses, pubs, bars, residential hotels, malls, airport lounges, clubs or other places of public amusements or entertainment;”

(b) after clause (ib), so substituted, the following clause shall be inserted, namely: —

“(ic) “**commercial subscriber**” means any person who receives broadcasting services or cable services at a place indicated by him to a cable operator or multi-system operator or direct to home operator or head end in the sky operator or Internet Protocol television service provider, as the case may be, and uses such services for the benefit of his clients, customers, members or any other class or group of persons having access to his commercial establishment;”

(c) for the clause (ma), the following clause shall be substituted, namely: —

“(ma) “**ordinary subscriber**” means any subscriber who receives broadcasting services or cable services from multi system operator or cable operator or direct to home operator or Internet Protocol television service provider or head end in the sky operator, as the case may be, and uses the same for his domestic purposes;”

(d) for the clause (na), the following clause shall be substituted, namely: —

“(na) “**subscriber**” means a person who receives broadcasting services or cable services from a multi system operator or cable operator or direct to home operator or Internet Protocol television service provider or head end in the sky operator at a place indicated by him to the multi system operator or cable operator or direct to home operator or Internet Protocol television service provider or head end in the sky operator, as the case may be, without further transmitting it to any person and includes ordinary subscribers and commercial subscribers, unless specifically excluded;”

3. In regulation 13.2A.1 of the principal regulation, the second proviso and the Explanation appearing at the end shall be deleted.

SUDHIR GUPTA, Secy.

[ADVT III/4/Ext./142/14]

Note.1—The principal regulation was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* notification No. 8-26/2004-B&CS dated 10th December 2004, No. 3-57/2005-B&CS dated 3rd March 2005, No. 11-13/2006-B&CS dated 24th August, 2006, No. 6-4/2006-B&CS dated 4th September 2006, No. 4-54/2007-B&CS dated 3rd September 2007, 3-21/2009-B&CS dated 17th March 2009, No. 6-7/2010-B&CS dated 30th July, 2010 and No. 6-11/2014 - B&CS dated the 10th February, 2014.

Note.2—The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Eighth Amendment) Regulation, 2014 (8 of 2014).

Annexure

Explanatory Memorandum

Background

1. The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) was entrusted with the responsibility of regulating ‘broadcasting and cable TV’ services in January, 2004. An interim Tariff Order was issued on 15.01.2004, which provided that the cable charges prevailing on 26.12.2003 shall be the ceilings at the respective levels. Thereafter, following extensive consultations, a detailed Tariff Order was issued on 01.10.2004. This order, while maintaining the sanctity of the ceiling of cable TV charges prevailing on 26.12.2003, also provided a window for introduction of new pay channels and conversion of existing Free-to-Air (FTA) channels to ‘pay channels’ subject to prescribed conditions. The underlying objective of these Tariff orders was to give relief and protection to consumers of broadcasting and cable TV services from frequent hikes in cable TV charges.

2. Subscribers of broadcasting and cable TV services are basically of two kinds. First, there are ordinary subscribers who consume TV services domestically for their own pleasure. The second group comprises commercial subscribers who obtain TV services for the benefit of their clients, customers etc., at their commercial establishment. While issuing the Tariff Orders in 2004, as mentioned above, the Authority, however, did not differentiate between ordinary and commercial subscribers.

3. The matter pertaining to tariffs for commercial subscribers has been under judicial scrutiny since 2005, before the Hon’ble Telecom Disputes Settlement Appellate Tribunal (TDSAT), when Hotels and Restaurants Association (Western India) (HRAWI), a sister association of Federation of Hotel and Restaurant Associations of India (FHRAI), challenged differential tariffs imposed by some broadcasters. The Hon’ble TDSAT disposed of these petitions *vide* its judgment dated 17.01.2006 wherein it concluded that the members of the petitioner associations couldn’t be regarded as subscribers or consumers. It also asked the Authority to consider whether it was necessary or not to fix tariff for commercial cable TV subscribers.

4. As an interim measure, on 07.03.2006, the Authority issued an amendment to the principal Tariff Order of 01.10.2004. This Tariff Amendment Order defined the terms ‘Ordinary cable subscriber’ and ‘Commercial cable subscriber’. In the meanwhile, the aforesaid judgment of the Hon’ble TDSAT was appealed by the Associations of Hotels and Restaurants before the Hon’ble Supreme Court. In an interim order on 19.10.2006, the Hon’ble Supreme Court directed the Authority to carry out the processes for framing the tariff under Section 11 of the TRAI Act, independently and not relying on or on the basis of any observation made by TDSAT. In its final order on 24.11.2006, the Hon’ble Supreme Court confirmed its interim orders and stated that it did not agree with the opinion of the Hon’ble

TDSAT that the Authority should also consider whether it is necessary or not to fix tariff for commercial cable TV subscribers.

5. Based on the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 19.10.2006, the Authority issued two Tariff Amendment Orders, on 21.11.2006, applicable to commercial subscribers in non-CAS and CAS areas, respectively. This tariff amendment order categorized commercial subscribers into the following two groups, namely: —

- (a) A specified category of commercial subscribers comprising—
 - (i) Hotels with rating of 3 stars and above;
 - (ii) Heritage hotels (as defined by the Department of Tourism, Government of India);
 - (iii) Any hotel, motel, inn or commercial establishment providing board & lodging and having 50 or more rooms; and
- (b) All other commercial subscribers (not falling under the specified category of commercial subscribers).

6. The tariff for cable TV services for the specified category of commercial subscribers was to be mutually determined by the parties. However, the tariff for commercial subscribers not falling in the specified categories (coming under the second category) was subject to the same charges as ordinary cable subscribers and thus the ceiling of rates prevailing as on 26.12.2003 was made applicable to them. The tariff amendment order also provided that whenever a commercial cable TV subscriber belonging to either of the two categories uses the programme of a broadcaster for public viewing by fifty or more persons on the occasion of special events at a place registered under the Entertainment Tax Act, the tariff will have to be mutually decided between the parties concerned.

7. These orders too were appealed against in the Hon'ble TDSAT by way of appeals [Appeal No.17(C) of 2006 - East India Hotel Ltd. Vs. TRAI & Ors. and Appeal No. 18 (C) of 2006 - The Connaught Prominent Hotels Limited vs. TRAI & Ors] by the hotels and their associations. The Hon'ble TDSAT passed its judgment on 28.05.2010 in the two appeals filed by the hotels against the tariff amendment orders dated 21.11.2006. The operative portion of the judgment of the Hon'ble TDSAT read:

“We, therefore, are of the opinion that it is a fit case where the impugned orders are required to be set aside. We direct accordingly. We, however, do not wish to issue any direction with regard to the refund of any amount but we would request the Authority to consider the case of commercial establishments once over again in a broad based manner”.

8. In sum, the sub-classification of commercial consumers into two categories was struck down by the Hon'ble TDSAT. Aggrieved by the TDSAT judgement dated 28.05.2010, M/s. ESPN Software India Pvt. Ltd. filed an appeal (CA No. 6040-41 of 2010 -M/s. ESPN Software India Pvt. Ltd. Vs. TRAI and Ors.) in the Supreme Court. The judgment of the Hon'ble Supreme Court, dated 16.04.2014, in this case, directs as follows:

“..... we direct that for a period of three months, the impugned tariff, which is in force as on today, shall continue. Within the said period, TRAI shall look into the matter de novo, as directed in the impugned judgment, and shall re-determine the tariff after hearing the contentions of all the stakeholders....”

9. Accordingly, as directed by the Hon'ble Supreme Court in its judgment dated 16.04.2014, TRAI initiated a consultation process, as part of a de novo exercise, and issued a Consultation Paper (CP) on 11.06.2014 seeking comments/views of the stakeholders. The CP discussed and raised related consultation issues pertaining to various alternatives for tariff stipulations for the commercial subscribers, manner of offering of TV services to them, the definition of the 'commercial establishment', 'shop' and 'commercial subscriber', and sub-categorization of the commercial subscribers into similarly placed groups. In response to the CP, 24 stakeholders submitted their views/comments to the Authority. Subsequently, to further discuss the issues involved, an Open House Discussion (OHD) was also held at Delhi on 4th July, 2014, wherein 59 stakeholders participated in the discussions.

10. This interconnection regulation is being notified after analyzing all the issues involved and the inputs received from various stakeholders.

Analysis of Issues

Definition of commercial subscribers, commercial establishment and shops

11. Draft definitions of commercial subscriber, commercial establishment and shops were discussed in the CP and views/comments of the stakeholders were solicited.

Stakeholder comments

12. Several broadcasters including the two prominent broadcasters, a broadcasting industry association, a Hotel industry association as well as a couple of cable TV operator associations have broadly agreed with the draft definitions. Some of them have pointed out that the 'profession' appearing in the definition of 'commercial establishments should be

deleted as some court decisions have held that the premises of doctors, lawyers, engineers etc. should not be considered commercial establishments. Some other broadcasters have stated that shops, factories and public viewing areas should be included in the definition of 'commercial establishment'. It was also suggested by a broadcaster that 'publishing' should also be included in the definition of 'commercial establishments'. An association of broadcasters and some other stakeholders from the broadcasters fraternity have put forth the view that any premise, indoor or outdoor, that is not a domestic premise should be categorized as commercial and commercial subscribers be defined in an all inclusive manner to include all subscribers except residential subscribers.

13. The majority of the distribution platform operators, cable and DTH, as well as a hotel and restaurant industry association are of the view that there is no need to make a distinction between ordinary and commercial subscribers and all subscribers should be treated at par. It has also been suggested to include the concept of commercial purpose and/or commercial exploitation into the definition of commercial establishment. Another industry association has proposed that commercial subscriber should be defined as the one who uses TV signals as its business or commercial activity or part thereof, irrespective of whether TV channels are charged or not from the viewers/audience.

Analysis

14. Taking into account the views of the stakeholders, the definition of 'commercial establishment' has been included and the definition of 'commercial subscriber' has been accordingly amended. This is also in line with the tariff prescription and the manner of offering of television services to the commercial subscribers, which have been discussed in subsequent paragraphs.

Tariff for Commercial subscribers

15. In the CP, the following four alternatives were discussed for prescribing tariff for commercial subscribers, seeking views/comments of the stakeholders:

- (i) The tariff for commercial subscribers is the same as that for ordinary subscribers.
- (ii) The tariff for commercial subscribers has a linkage with the tariff for ordinary subscribers.
- (iii) The tariff for commercial subscribers has no linkage with the tariff for ordinary subscribers but there are some protective measures prescribed to protect all the stakeholders such as mandatory a-la-carte offering, conditions to prevent perverse a-la-carte pricing vis-à-vis bouquet rates etc.
- (iv) The tariff for commercial subscribers is kept under total forbearance.

Stakeholder comments

16. Hotel industry associations and almost all distribution platform operators (DPOs) have advocated for adoption of the first alternative discussed in the CP i.e. the tariff for commercial subscribers should be same as that prescribed for the ordinary subscribers. To support their view, the main arguments put forth have been - (i) the ultimate consumer/viewer is the same whether the TV services are availed at the domestic premises of the consumer or in a hotel or hospital or any other commercial establishment, (ii) a consumer does not go to such commercial establishment specifically to view TV channels (iii) there is no extra cost to the broadcaster for production of content and its distribution in both the cases and the content/quality of signal remains the same. Some of them further stated that, in cases where the consumer goes to a commercial establishment specifically to avail TV services and pays for it, the tariff may be different from that for the ordinary subscribers.

17. On the other hand, all broadcasters and their representative bodies are of the view that the fourth alternative, prescribing total forbearance on tariff for commercial subscribers, be adopted. The main arguments presented by them in this regard are - (i) the TV services are basically non-essential services and, therefore, need not be regulated, (ii) in many international markets, differential pricing is done for the commercial subscribers, (iii) commercial subscribers exploit the TV signals for commercial gains, therefore, the broadcasters are entitled to a fair share of the same. In response to a query during the OHD, an Association of broadcasters has indicated that the total revenue of the commercial subscribers that are 'known' to subscribe to television are estimated at 1.5-2.2% of total distribution revenues.

18. A head end in the sky (HITS) operator has suggested for prescription of the second alternative which provides that there should be a certain linkage between the tariff for ordinary and commercial subscribers. A broadcaster and a couple of cable operator associations have expressed their preference for the third alternative. It has also been suggested by a multi system operator (MSO) that a broadcaster should prescribe the retail price of its channels for different categories of commercial subscribers and the revenue share for different stakeholders in the value chain should be determined by TRAI.

Analysis

19. The end consumer, whether at his domestic premises or at any commercial establishment, gets to view the same content with same quality of signals. In both the cases, the cost to the content owner (broadcaster) and the DPO, for supplying the signals, per se, does not vary on account of where the signals are supplied - at the domestic premises or the

commercial establishment. Moreover, The Hon'ble Supreme Court in its judgment dated 24.11.2006 in appeal (Civil) 2061 of 2006 Hotel and Restaurants Association and Anr Vs. Star India Pvt. Ltd. and Ors has, amongst others, observed as under:

"....The owners of the hotels take TV signals for their customers/guests. While doing so, they inter alia provide services to their customers. An owner of a hotel provides various amenities to its customers such as beds, meals, fans, television, etc. Making a provision for extending such facilities or amenities to the boarders would not constitute a sale by an owner to a guest. The owners of the hotels take TV signals from the broadcasters in the same manner as they take supply of electrical energy from the licensees. A guest may use an electrical appliance. The same would not constitute the sale of electricity by the hotel to him. For the said purpose, the 'consumer' and 'subscriber' would continue to be the hotel and its management. Similarly, if a television set is provided in all the rooms, as part of the services rendered by the management by way of an amenity, wherefor the guests are not charged separately, the same would not convert the guests staying in a hotel into consumers or subscribers....."

The said judgment further quotes another judgment of the Hon'ble Supreme Court (in *The State of Punjab v. M/s. Associated Hotels of India Ltd.* [(1972) 1 SCC 472]) on similar issue, which is reproduced as under:

".... When a traveller, by plane or by steam-ship, purchases his passage-ticket, the transaction is one for his passage from one place to another. If, in the course of carrying out that transaction, the traveller is supplied with drinks or meals or cigarettes, no one would think that the transaction involves separate sales each time any of those things is supplied. The transaction is essentially one of carrying the passenger to his destination and if in performance of the contract of carriage something is supplied to him, such supply is only incidental to that services, not changing either the pattern or the nature of the contract. Similarly, when clothes are given for washing to a laundry, there is a transaction which essentially involves work or service, and if the laundryman stitches a button to a garment which has fallen off, there is no sale of the button or the thread. A number of such cases involving incidental uses of materials can be cited, none of which can be said to involve a sale as part of the main transaction."

20. From the observations of the Hon'ble Supreme Court, cited above, it is clear that provision of TV services in a commercial establishment is only incidental to the service that the commercial establishment is providing to its clients. It cannot be construed as re-distribution or re-sale of TV services. In any case, there is no re-transmission. In sum, the question as to who is the subscriber has been settled through this judgment. It has also been settled by the said judgment that any service rendered to a guest by way of an amenity, wherefor the guests are not charged separately, the same would not constitute as sale of the said service to the guest. Further, this judgment specifically refers to the subject in hand. **Accordingly, the Authority was of the view that in the rates of TV services, which are per TV set in the analog and per set top box (STB) in case of digital addressable systems, there should be no differentiation between an ordinary subscriber and a commercial subscriber i.e. in both the cases the charges should be same and as per TV set (in analog systems) and per STB (in digital addressable systems).**

21. However, in case, the commercial establishment specifically charges extra to its clients/visitors on account of viewing of channels at its premises, there is a case for broadcasters to have a share in such revenue of the commercial establishment. Therefore, where the commercial establishment is earning extra revenue from its clients specifically on account of providing TV services, the rates should be based on mutual negotiations between the broadcaster and the commercial subscriber. In such cases also, the commercial subscriber would be required to obtain such signals of TV channel through a DPO/cable operator only. In view of the above, suitable amendments have also been made in the tariff orders, applicable for both the addressable and non-addressable systems.

Manner of offering TV channels to the commercial subscribers

22. Three models of offering of TV channels to commercial subscribers were discussed in the CP. The first model envisages that the commercial subscriber enters into agreement with the broadcaster and obtains signals either from the broadcaster itself or a DPO designated by the broadcaster. In the second model, the commercial subscriber is to enter into agreement with the DPO and obtain the signals while DPO and broadcasters have their own mutually agreed arrangements. The third model discussed in the CP is a combination of the first and second models.

Stakeholder Comments

23. Almost all the broadcasters and their representative bodies and agents have stated that only the first model is viable and should be adopted. While suggesting a detailed procedure for implementation of this model they have reasoned that – (a) the second model is prone to commercial subscribers not getting signal because of potential breakdown of negotiations between broadcasters and DPOs and (b) the third model is prone to confusion, as both broadcasters and DPOs would be allowed to provide Reference Interconnect Offers(RIOs).

24. Almost all the DPOs have suggested adoption of second model. A couple of cable TV operator associations have opined that the regulator should fix the MRP based on which the broadcasters and DPOs make the RIO. However,

broadcasters should not identify the DPO through which the commercial subscriber should get the signals of the broadcaster. They have also stated that in cases where commercial subscribers have their own headend, the broadcasters can directly negotiate with the commercial subscribers as per RIO. Another cable operator association has stated that the broadcaster and commercial subscribers should negotiate the rates while the DPO should give the services at the same rate as for ordinary subscriber.

25. One of the hotel and restaurant industry associations has stated the first model should not be adopted, while another hotel industry association has expressed its preference for the third model.

Analysis

26. The guideline for downlinking of TV channels in India prescribe as under:

"5.6. The applicant company shall provide Satellite TV Channel signal reception decoders only to MSOs/Cable Operators registered under the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 or to a DTH operator registered under the DTH guidelines issued by Government of India or to an Internet Protocol Television (IPTV) Service Provider duly permitted under their existing Telecom License or authorized by Department of Telecommunications or to a HITS operator duly permitted under the policy guidelines for HITS operators issued by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India to provide such service."

So, the broadcaster cannot supply signals directly to subscribers, including the commercial subscribers. Broadcasters should supply their signals through a DPO. It would also ensure competition in the market if a commercial subscriber can obtain TV signals from any MSO or its linked local cable operator /DTH operator etc. operating in his area. Accordingly, definitions of 'ordinary subscriber' and 'subscriber' have been suitably amended.

Sub-categorization of commercial subscribers

27. In the CP, the issue regarding sub-categorization of commercial subscribers into similarly placed groups and fixing the tariff therefor was discussed and views of the stakeholders were sought. Almost all the stakeholders, across all the segments, are of the view that any such sub-categorization and fixing of tariff for such sub-categories may not be the appropriate way forward.

Analysis

28. In view of the tariff prescription and the provisions regarding manner of offering of TV signals to the commercial subscribers, there is no need for sub-categorization of the commercial subscribers into similarly placed groups for the purpose of prescription of tariff dispensation for commercial subscribers. The only distinction required is to place the commercial subscribers into two broad classes – (i) those who offer television services/programmes as part of amenities to their guests and (ii) those who charge for the same in the manner as discussed in para 21 above. In view of the above, regulation 13.2A.1 has been suitably amended.